



आज लोकतंत्र को सफल करने वालों का तैयार करने वालों की आवश्यकता है जो इस भारत के लोकतंत्र को सही दिशा प्रदान कर सकें।

Today we need such people who can prepare defenders of democracy who in turn can give right direction to Indian democracy.

आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज

दैनिक विश्व परिवार

● अंक : 10 ● वर्ष : 14 ● रायपुर, गुरुवार 09 जुलाई 2026 ● पृष्ठ : 08 ● मूल्य : 3 रूपए ● संस्थापक : कीर्तिशेष- श्री कैलाश चन्द्र जैन

साय कैबिनेट की बैठक में कई विधेयकों को मिली मंजूरी

■ एनटीपीसी सहित अन्य सीपीएसयू से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी

रायपुर (विश्व परिवार)। मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपकरणों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मॉडल व्यवस्था लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से एनटीपीसी सहित अन्य सीपीएसयू से विद्युत आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप हो सकेगी। राज्य शासन पर इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि



वितरण कंपनी द्वारा भुगतान की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी तथा आवश्यक होने पर पहले लेटर ऑफ क्रेडिट की व्यवस्था प्रभावी रहेगी। मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिका बल (बस्तर फ़र्टस), फ़ाइटर आरक्षक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम, 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 के

प्राारूप का अनुमोदन किया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और समकालीन बनाया गया है। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि का प्रावधान लागू करने से अध्येयनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जा सकेंगे। इसमें

आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को योजनीय एवं सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन से राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिपरिषद् ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्राारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन के माध्यम से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त करने के साथ ही उससे संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी द्वितीय अपीलों के मामलों में उल्लेखनीय प्रशासन अधिक प्रभावी होगा, करदाताओं को सुविधा मिलेगी साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

वाणिज्यिक कर अधिकरण की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संशोधन के बाद अधिकरण में लंबित प्रकरणों का स्थानांतरण राजस्व मंडल को किया जाएगा, जिससे अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित एवं अधिक प्रभावी हो सकेगी। मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्राारूप को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य जीएसटी कानून को सरल बनाना, अनुपालन संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाना तथा करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे कर प्रशासन अधिक प्रभावी होगा, करदाताओं को सुविधा मिलेगी साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

भारत की विकास यात्रा यानी 1.4 अरब लोगों की आगे बढ़ती उम्मीदें : प्रधानमंत्री मोदी

जकार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार चुनौतियों और संकटों के बावजूद भारत एक के बाद एक सुधारों के जरिए तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का अर्थ 1.4 अरब लोगों की आगे बढ़ती उम्मीदें और आकांक्षाएँ हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज गांव से लेकर शहर तक हर भारतीय में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने का विश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति अचानक नहीं हुई है, बल्कि लगातार किए गए सुधारों और बेहतर प्रदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के मंत्र के साथ देश आगे बढ़ रहा है। इसी सोच ने भारत को तेजी से बदलने और वैश्विक स्तर पर मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की कार्यक्रम में



मौजूदगी का स्वागत करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच गहरे रिश्तों का प्रतीक है। उन्होंने इंडोनेशिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय भारत और इंडोनेशिया के बीच मित्रता को मजबूत कड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महानदी में केले के तने से बनी नावें तैराने की परंपरा, वायांग कुलित के माध्यम से महाभारत का मंचन और देवी श्री की पूजा जैसी परंपराएं भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों की जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का रिश्ता जितना प्राचीन है, उतना ही समृद्ध भी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया

और पूरे आसियान क्षेत्र में विकास और समृद्धि का मजबूत साझेदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देशों के पास रुकने का समय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक विकास की प्रमुख ताकत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट जैसे कठिन दौर में भी भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार बनी रही और देश ने मजबूती के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। प्रधानमंत्री ने मिला स्नेह और आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि भारतीय समुदाय का प्रेम और उत्साह उन्हें बेहद प्रभावित कर गया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की कार्यक्रम में मौजूदगी के लिए भी धन्यवाद दिया और कहा कि उनके संबोधन में भारत के प्रति आत्मीयता स्पष्ट रूप से दिखाई दी।

आईएस और राज्य सेवा के अधिकारियों का तबादला



■ एका को सुडा का अतिरिक्त प्रभार, गजेंद्र सिंह ठाकुर राजस्व विभाग में उप सचिव

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से देर रात आदेश जारी हुआ है। जारी आदेश में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। सीनियर अधिकारी रिमिजियस एका को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ राज्य शहरी विकास अधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग का उप सचिव बनाया गया है। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुरुचि सिंह को नगर

पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। वहीं, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम. भागवत को जिला पंचायत देवाड़ा, तन्मय खन्ना को जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

राजीव कुमार को उच्च शिक्षा संचालनालय में पोस्टिंग

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में भी बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इंद्रजीत बर्मन को स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। राजीव कुमार पांडेय को उच्च शिक्षा संचालनालय में पदस्थ किया गया है। भारतीय चंद्राकर को मार्कफेड, दिनेश कुमार नाग को छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाय कॉर्पोरेशन और नयनतारा सिंह तोमर को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पुणे-दिल्ली में इमारत ढही, कई लोग दबे, रेस्क्यू जारी



पुणा। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को भारी बारिश के कारण कचरे का पहाड़ 3 मंजिला इमारत पर गिर गया, जिससे कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग ढह गई। हदसे में 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के रोहिणी में भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। पुणे के खंडाला में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से एक सिस्कोरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसका साथी अब भी लापता है। उधर, गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच तक बारिश हुई, जिससे 85 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जुलाई 1941 में 18 इंच बारिश हुई थी सूरत में बाद से शॉपिंग मॉल की एक मंजिल पानी में डूब गई। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। करंट लगने, पेड़ और बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हुई। 3400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को खाने-पीने की परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश के चलते दिल्ली-जयपुर ह 11-48 धंस गया है, जिसके कारण 10 किमी लंबा जाम लगा गया। एक स्कूल बस भी नाले में फंस गई।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक देश में उच्च शिक्षा के स्तर को और बेहतर करेगा : अग्रवाल

■ विकसित भारत के सपनों को साकार करने में विधेयक होगा मददगार

रायपुर/नई दिल्ली। सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025' देश में उच्च शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने में मददगार साबित होगा।



सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बैठक में विधेयक के सभी प्रावधानों पर बिन्दुवार गहन विचार विमर्श कर विधेयक को अंतिम रूप दिया गया। संसद के आगामी मानसून सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा। सांसद अग्रवाल के अनुसार विधेयक देश की नई शिक्षा नीति को जनता के लिए और

उपयोगी और सुगम बनाने में पूरी तरह सहयोग करेगा। यह विधेयक देश में उच्च शिक्षा (Higher Education) के स्तर को न सिर्फ नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) को और अधिक सुगम, व्यावहारिक और उपयोगी बनाने में मौल का पथर साबित होगा।

राष्ट्रीय उपलब्धियों से रोशन छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन की विद्युत कंपनियों ने अर्जित की राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धियाँ



छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड



छत्तीसगढ़ टैप एंड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड



सी एस पी जी सी एल

14वीं एकीकृत रेटिंग एवं रैंकिंग विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में CSPDCL को 'A' ग्रेड प्राप्त

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्कृष्टता पुरस्कार- केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा "सर्वाधिक वेंडर पंजीयन" श्रेणी में द्वितीय स्थान

3 राष्ट्रीय उत्पादन प्रदर्शन में तृतीय स्थान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की रिपोर्ट में CSPGCL के डीएसपीएम ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान

A++ सर्वोच्च A++ रेटिंग बरकरार पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) के मूल्यांकन में CSPTCL को पुनः A++ रेटिंग



• समर्पण • सेवा
• विश्वास • विकास



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



विश्वसनीय बिजली



उत्कृष्ट सेवा



हरित भविष्य

O/o DGM (PR) CSPTCL द्वारा जारी

Shumad-4839/1

बालक का प्रथम पाठशाला उसका अपना घर और माता-पिता प्रथम गुरु होते हैं - गोपाल सिंह विद्रोही

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 85 पदों हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी, 24 जुलाई तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

वी डी एस महागांवा सूरजपुर में शाला प्रवेश उत्सव पर बच्चों ने नृत्य कला का किया प्रदर्शन अतिथियों ने पौधे लगाए



सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- बीडीएस कॉन्वेंट स्कूल महागांवा सूरजपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने अपनी विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया।

आयोजन के मुख्य अतिथि शैलेश गोयल उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद सूरजपुर। विशिष्ट अतिथियों के रूप में पारस राजवाड़े, पार्षद (वार्ड क्रमांक 2), कार्यक्रम के अध्यक्षता सूरजपुर जिला के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह विद्रोही, युवा पत्रकार राजेंद्र पासवान, विश्रामपुर; श्री कृष्णा मंगल, तथा आचार्य श्री प्रणय सिंह राणा मंचासिन थे।

उक्त अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका सूरजपुर के उपाध्यक्ष शैलेश गोयल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई में अभिरुचि लाने का यह शाला प्रवेश उत्सव छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी जोर जोर से प्रदेश के सभी विद्यालयों में मनाने का अभियान चालू की है जिसका लाभ भी बेहतर प्राप्त हो रहा है। बच्चों को पढ़ने में

सभी अतिथियों द्वारा विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का पौधा रोपण कर बच्चों और पालकों में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।

उक्त अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका सूरजपुर के उपाध्यक्ष शैलेश गोयल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई में अभिरुचि लाने का यह शाला प्रवेश उत्सव छत्तीसगढ़ सरकार बड़ी जोर जोर से प्रदेश के सभी विद्यालयों में मनाने का अभियान चालू की है जिसका लाभ भी बेहतर प्राप्त हो रहा है। बच्चों को पढ़ने में

अभिरुचि, विद्यालय जाने के लिए उत्साहित रहते हैं। माता-पिता को भी चाहिए कि उन्हें विद्यालय जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे। माता-पिता अपना कार्य को छोड़कर प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय तक बच्चों को छोड़े तभी विद्यालय के शिक्षक उन्हें अच्छा देश का नागरिक बन सकते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। माता-पिता को आदर करना सीख सकते हैं, आगे चलकर यह बच्चे हमारे देश की दिशा तय करेंगे

इसलिए हम सब को जिम्मेदारी होती है जो वर्तमान के इन नौनिहाल बच्चों में नैतिकता संस्कार के साथ विद्या अध्ययन करने हेतु प्रेरित करें जिसके लिए माता-पिता एवं गुरु का ज्यादा जिम्मेदारियां होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन से पालक भी सीख कर अपने बच्चों को संस्कारीत करेंगे तथा विद्यालय भेजने हेतु अपने दायित्व और कर्तव्य का पालन करेंगे तभी उनका नाम रोशन कर सकते हैं। भारत का अनुशासित नागरिक बन सकता है और माता पिता घर परिवार समाज सब का सेवा कर सकता है। आने वाला कल उसके कंधे पर होगा इसलिए उसे आज से ही तैयार करने हम सब को जिम्मेदारी है।

युवा पत्रकार राजेंद्र पासवान ने कहा कि गुरु जी की मार पीट मां-बाप की फटकार से ही बच्चों में बेहतरीन संस्कार डालता है। गुरुजी की डांट फटकार से माता-पिता को नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि गुरुजी बच्चों का दुश्मन नहीं है बच्चों को संवारने के लिए उन्हें बाहर से फटकार लगाते हैं और अंदर से स्नेह का मैप लगते हैं इस बात को परिजनों को समझना होगा तभी उनके बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

आयोजन की अध्यक्षता कर रहे सूरजपुर जिला के वरिष्ठ पत्रकार गोपाल सिंह विद्रोही ने कहा कि भय बिन प्रीत न होय गोसाईं

अर्थात् बिना भय का प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है। भय से ही अनुशासन आता है भय दिखाने के लिए ही कानून बना है, इसी तरह विद्यालय में भय का होना अति आवश्यक है। श्री विद्रोही ने कहा कि बालक का प्रथम पाठशाला उसका अपना घर होता है और माता-पिता गुरु। बच्चा पहले अपने घर में ही चलना फिरना बोलना उठना बैठना तमाम बातें अपने माता-पिता से सीखता है तब मां उसे विद्यालय जाने का बोध कराती है फिर गुरु का बारी आती है। गुरु कुम्हार की तरह बच्चों का आकार देते हैं इसलिए पालक को शिक्षकों की डांट फटकार पर नाराज नहीं होना चाहिए। शिक्षक बच्चों का कभी अहित नहीं चाहते इन्होंने कहा देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी संचालित है बाद में स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्रियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और शिक्षा का स्तर गिरता गया। हमें गुरुकुल का अनुशासन एवं संस्कार और आधुनिक शिक्षा से बच्चे स्वावलंबी बन सकते हैं इसी तरह की शिक्षा बच्चों के अंदर देने की जरूरत है।

कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों को समय प्रदान करने एवं कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हृदय से विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षिकाओं ने आभार व्यक्त किया।

विश्रामपुर की रुक्मिणी पाल अब डॉ रुक्मिणी पाल के नाम से जानी जाएगी मिली इन्हें पी-एच.डी. की उपाधि

भारत की विभीषिका और हिन्दी उपन्यास विषय पर पूर्ण किया शोध

गोपाल सिंह विद्रोही



रुक्मिणी पाल ने यह शोध ग्रंथ शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ एवं शासकीय नवीन महाविद्यालय नागपुर के प्राचार्य डॉ. रामकिंकर पांडेय के शोध निदेशान में पूर्ण किया। अपने शोध में उन्होंने हिन्दी उपन्यास साहित्य में भारत की विभीषिका के चित्रण का, विशेष रूप से स्त्री जीवन के संदर्भ में, गहन अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उल्लेखनीय है कि साहित्य के इस संवेदनशील एवं गंभीर विषय पर किया गया यह शोध कार्य नारी जीवन के संघर्षों और अनुभवों को साहित्यिक दृष्टि से समझने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। रुक्मिणी पाल की इस शैक्षणिक उपलब्धि से क्षेत्र का गौरव बढ़ा है तथा यह संपन्नता अन्य शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी है।

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, अम्बिकापुर द्वारा विश्रामपुर निवासी रुक्मिणी पाल को भारत की विभीषिका और हिन्दी उपन्यास (स्त्री जीवन के विशेष संदर्भ में) विषय पर पी-एच.डी. की उपाधि प्रदान की है। इस उपलब्धि के साथ ही वे अब डॉ. रुक्मिणी पाल के नाम से पहचानी जाएंगी। उनकी इस संपन्नता पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है तथा परिजनों, शिक्षाविदों एवं शुभचिंतकों की ओर से बधाइयों का ताता लगा हुआ है।

सूरजपुर जिले में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- खरीफ सीजन को देखते हुए जिले के किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी जानकारी के अनुसार 7 जुलाई 2026 की स्थिति में जिले की समितियों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

जिले में कुल 9,515.13 मैट्रिक टन यूरिया, 2,727.45 मैट्रिक टन 12:32:16, 3,406.70 मैट्रिक टन डीएपी, 1,659.35 मैट्रिक टन सुपर फॉस्फेट, 587.85 मैट्रिक टन पोटाश तथा 6,065.10 मैट्रिक टन 20:20:0:13 का भंडारण किया गया है।

इनमें से अब तक 7,596.40 मैट्रिक टन यूरिया, 1,788.50 मैट्रिक टन 12:32:16, 2,228.90 मैट्रिक टन डीएपी, 787.85 मैट्रिक टन सुपर फॉस्फेट, 319.90 मैट्रिक टन पोटाश तथा 3,983.55 मैट्रिक टन 20:20:0:13 का किसानों को वितरण किया जा चुका है।

वितरण के बाद समितियों में 1,918.73 मैट्रिक टन यूरिया, 938.95 मैट्रिक टन 12:32:16, 1,177.80 मैट्रिक टन डीएपी, 871.50 मैट्रिक टन सुपर फॉस्फेट, 267.95 मैट्रिक टन पोटाश तथा 2,081.55 मैट्रिक टन 20:20:0:13 शेष उपलब्ध है।

कृषि विभाग ने किसानों से आवश्यकतानुसार निकटतम सहकारी समिति से उर्वरक प्राप्त करने तथा निर्धारित अनुशासित मात्रा में संतुलित उर्वरकों के उपयोग की अपील की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की जिला बैठक में विभिन्न विषयों पर बनी रणनीति

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन सूरजपुर की जिला बैठक का आयोजन सूरजपुर में किया गया जिसमें पूर्व सेवा गणना, टेड की अनिवार्यता, क्रमोन्नति समयमान के विकल्प चयन, लिखित पदोन्नति, 1 ग्नाथ एप में उपस्थिति सहित अन्य विषयों पर रणनीति बना कर प्रांतीय निर्देश पर कार्य करने का निर्णय लिया गया।

इस अवसर पर टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री रंजय सिंह जिलाध्यक्ष भूपेश सिंह जी ने बताया कि पूर्व सेवा गणना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक टीचर्स एसोसिएशन एलबी संवर्ग की प्रमुख मांग को लेकर संघर्ष करेंगे साथ ही विभागीय टेड परीक्षा आयोजित कर प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में अध्यापनरत शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग कर आवश्यक रणनीति बनाएंगे, क्रमोन्नति समयमान विकल्प चयन पर चर्चा के साथ इंटरनेट विहीन क्षेत्रों में ड्यूटी पेप में उपस्थिति की जटिलता पर चिंता जाहिर कर समुचित उपाय करने की मांग रखने का निर्णय लिया गया, ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षकों को मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश के विरुद्ध सभी को अर्जित अवकाश प्रदान करने की मांग प्रांत स्तर से रखने, प्रधान पाठक प्राथमिक



शाला, शिक्षक, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, व्याख्याता, प्राचार्य के रिक्त पदों पर समय सारणी बनाकर पदोन्नति प्रदान करने की मांग पर चर्चा किया गया, लिखित हक्क की राशि की गणना कर खाता में जल्द अंतरण करने सभी विकास खण्ड में शिक्षा अधिकारी से चर्चा करने सहित स्थानीय अन्य समस्याओं पर विस्तार पर चर्चा किया गया एवं प्रांतीय निर्देश पर सभी कार्य को प्रमुखता से करने का निर्णय लिया गया।

जिला की बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री रंजय सिंह, जिलाध्यक्ष भूपेश सिंह, रामचंद्र सोनी, सुरविंद गुरू, चन्द्रविजय सिंह, बिजेन्द्र साहू, गौरी शंकर पांडेय, अनुज

राजवाड़े, दीपक झा, मिथिलेश पाठक, पीतांबर सिंह मरावी नागेन्द्र सिंह, चंद्रदेव चक्रधारी, उमेश गुर्जर, विजय कुमार सिंह, उमाकांत मिश्रा, बिजेन्द्र कुमार सिंह, शंभुनाथ मिंज, यदुवंश नारायण, निरंजन मरकाम, रोशन सिंह कंवर, अमरेश्वर सूर्यवंशी, लक्ष्मण लाल राजवाड़े, अशोक कुमार शाक्य, राजेश कुमार सिंह, ज्वालाला प्रसाद कुं, प्रेम दास गुप्ता, संजय कुमार कश्यप, सुशील केरकेट्टा, दिनेश कुमार सिंह, मनोज झा, ईश्वर प्रताप सिंह, श्रीमती मंजू टोपी, श्रीमती फौलक खाखा, शुभम शर्मा, कविंद्र साहू, धर्मेंद्र कुमार बरेंट, जितेंद्र सिंह, टेकराम राजवाड़े, बिनोद केराम, रामबरन सिंह, अरविंद तिवारी, लवकुश

आवास की राशि लेकर निर्माण नहीं करने वालों को दी गई समझाईश

66 हितग्राहियों की एसडीएम कार्यालय में पेशी, अगली तारीख तक आवास पूर्ण करने के निर्देश

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार)- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शासन से आवास निर्माण की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अधूरा छोड़ने वाले हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के लाभ बता कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर द्वारा ग्राम पंचायत केवरा, पार्वतीपुर, कनकनगर, सिलफिली, सिंधरा, भंडिया, सिलोटा, सेमराकला, मतिगढ़ एवं खेराडीह के ऐसे हितग्राहियों की एसडीएम कार्यालय में पेशी ली गई।

पेशी के दौरान कुल 66 हितग्राही उपस्थित हुए, जिन्होंने आवास निर्माण के लिए स्वीकृत राशि प्राप्त करने के बावजूद या तो निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है अथवा अब तक आवास पूर्ण नहीं कराया है। सुनवाई के दौरान एसडीएम ने सभी हितग्राहियों से एक-एक कर निर्माण



कार्य की स्थिति की जानकारी ली तथा योजना की राशि का सदुपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा में आवास पूर्ण करने के निर्देश दिए।

एसडीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन हितग्राहियों ने अभी तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, वे तत्काल कार्य शुरू करें और जिनके

आवास निर्माणधीन हैं, वे अगली पेशी तक हर हाल में निर्माण कार्य पूर्ण करें। साथ ही निर्देशित किया गया कि अगली सुनवाई में प्रत्येक हितग्राही अपने निर्मित आवास के फोटो लेकर आये। संबंधित अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी इसका सत्यापन करेंगे, ताकि निर्माण कार्य की वास्तविक स्थिति का परीक्षण किया जा सके। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक आवास निर्माण पूर्ण नहीं होगा, तब तक संबंधित हितग्राहियों को नियमित रूप से पेशी में उपस्थित होना पड़ेगा। जिला पंचायत सीईओ श्री बिजेन्द्र

सिंह पाटले ने पीएम आवास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य में लापरवाही अथवा राशि का अन्यत्र उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसी कारण प्रशासन लगातार समीक्षा कर निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहा है, ताकि सभी स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण करवाकर पात्र हितग्राहियों को योजना का वास्तविक लाभ दिलाया जा सके।

सिंह पाटले ने पीएम आवास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में योजना की राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य में लापरवाही अथवा राशि का अन्यत्र उपयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इसी कारण प्रशासन लगातार समीक्षा कर निर्माण कार्यों की निगरानी कर रहा है, ताकि सभी स्वीकृत आवास समय पर पूर्ण करवाकर पात्र हितग्राहियों को योजना का वास्तविक लाभ दिलाया जा सके।

संपादकीय अपनी सीढ़ी तैयार करने ही होगी.....

बिना अपनी जमीन तैयार किए चीन की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़कर विकसित होने की सोच समस्यारस्त है। विकास के लिए भारत को आखिरकार अपना मॉडल और अपनी सीढ़ी तैयार करनी ही होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अनंत गोयनका की ये राय अहम है कि भारत को चीन से बचने की कोशिश के बजाय उससे कारोबारी संबंध बढ़ाने चाहिए। मैनुफैक्चरिंग क्षमता की मजबूती, नवाचार को बढ़ावा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से अधिक गहराई से जुड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। फिक्की के सदस्य सीईओज के एक दल की पांच दिवसीय चीन यात्रा के बाद गोयनका चीन से तीन खास बातें कही: पहली, चीन कड़े मुकाबले वाले एक फाइटिंग रिंग की तरह है। वहां कंपनियां ऐसे 2-3 प्रतिशत की मार्जिन (मुनाफे) पर काम करती हैं। इस प्रतिस्पर्धा में सिर्फ कठोर और सर्वश्रेष्ठ कंपनियां ही टिक पाती हैं। दूसरी, वहां अनुसंधान एवं विकास और ऑटोमेशन उच्चतम स्तर पर हैं। कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश दास साल के भविष्य को ध्यान में रखकर करती हैं, ना कि किसी तिमाही नतीजे को देख कर। और तीसरी बात यह कि वहां सरकार एक मूक शेरधारक है। सस्ता कर्ज, जमीन, बिजली और नीतिगत सहयोग इस पैमाने पर मिलता है कि प्रति इकाई लागत और मुनाफे का गणित बदल जाता है। इस कारण दूसरे देशों की कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा का धरातल समान नहीं रह जाता। गोयनका की टिप्पणियां भारतीय कारोबारी सोच में बड़े बदलाव का संकेत हैं। भारतीय उद्योगपति अब इस भय से निकल गए हैं कि चीन भारत पर हावी हो सकता है। बल्कि राय यह उभरी है कि औद्योगिक विकास के अगले दौर में जाने के लिए चीनी आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ना आवश्यक हो गया है। लेकिन गोयनका का यह तर्क विवादास्पद है कि भारत को औद्योगिक विकास के पारंपरिक चरणों को छोड़ देना कर सीधे डिजिटल रूप से एकीकृत, कम इंसानी दखल वाले उत्पादन की ओर बढ़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हर विकसित देश ने ऑटोमेशन तब अपनाया, जब वह बड़े पैमाने पर उत्पादन को व्यवस्थित करना सीख चुका था। नीचे की सीढ़ियां छोड़कर भारत सीधे चोटी पर नहीं पहुंच सकता। यानी बिना अपनी जमीन तैयार किए चीन से जुड़कर विकसित होने की सोच समस्यारस्त है।

आलेख

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिरस्थाई विरासत: संस्थाएं, विचार और राष्ट्र निर्माण

लेखक: गजेंद्र सिंह शेखावत

इतिहास अक्सर महान नेताओं को उनके राजनीतिक संघर्षों के जरिए याद करता है। लेकिन राजनेताओं के चिरस्मरणीय योगदान राजनीति के दायरे तक ही सीमित नहीं होते। उनकी वास्तविक विरासत उनके द्वारा सृजित संस्थाओं, परिपोषित विचारों और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़े गए आदर्शों में होती है। राष्ट्र भारत केरी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्म दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उनके सार्वजनिक जीवन के एक ऐसे पहलू को स्मरण करना प्रासंगिक होगा जिसकी ओर व्यापक रूप से गौर करने की जरूरत है। यह पहलू है, राष्ट्र निर्माण की बुनियाद के रूप में संस्थाओं का सृजन करने की उनकी आजीवन प्रतिबद्धता। स्वतंत्र भारत का उदय सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष से नहीं हुआ। उसे विश्वविद्यालय बनाने थे जो नागरिकों को शिक्षित करने में सक्षम हों। ऐसी अनुसंधान संस्थाएं खड़ी करनी थीं जो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार कर सकें। उसे ऐसे उद्योग तैयार करने थे जो आर्थिक आत्मनिर्भरता पैदा कर सकें। सभ्यता की विरासत की रक्षा करने वाले सांस्कृतिक संभारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने वाली लोक संस्थाओं को तैयार करना था। डॉ मुखर्जी ने जल्दी ही समझ लिया था कि राष्ट्र का भविष्य सिर्फ दूरदृष्ट नेतृत्व ही निर्भर नहीं करता। यह उन मजबूत संस्थाओं पर भी निर्भर करता है जो नेताओं और सरकारों से ज्यादा टिकाऊ होंगी। उनका असाधारण शैक्षिक करियर उनके विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उन्होंने वैसे समय में यह कार्यभार संभाला जब उच्चतर शिक्षा भारत के बौद्धिक जागरण का केंद्र बन रही थी। उनके लिए विश्वविद्यालय सिर्फ छात्रक तैयार करने के स्थल नहीं थे। वे वैसे सुविज्ञ नागरिकों को गढ़ने वाले संस्थान थे जो सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी के साथ योगदान करने में सक्षम हों। उनकी राय थी कि शिक्षा को राष्ट्र निर्माण के वृहत्तर कार्य से अलग नहीं किया जा सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति के प्रति उनका समर्पण विश्वविद्यालयों के परिसर से कहीं आगे बढ़कर था। भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु की कोर्ट और कारोर्सिल के सदस्य के तौर पर, उन्होंने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में से एक को मजबूत बनाने में योगदान दिया। 1947 में, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पावर इंजीनियरिंग की आधारशिला रखी क्योंकि वे भली-भांति समझते थे कि स्वतंत्र भारत की आर्थिक प्रगति के लिए इंजीनियरिंग की शिक्षा और प्रौद्योगिकी क्षमता बहुत जरूरी होगी। नवाचार को मुख्य नीतिगत लक्ष्य बनाए जाने से बहुत पहले ही, उन्होंने यह समझ लिया था कि वैज्ञानिक उत्कृष्टता और औद्योगिक विकास ही देश की दीर्घकालिक मजबूती तय करेंगे। स्वतंत्रता के बाद, जब डॉ. मुखर्जी भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, तब इस दृष्टिकोण को व्यावहारिक रूप दिया गया। उन शुरुआती सालों में, नए नए आजाद देश के सामने एक औद्योगिक आधार तैयार करने की बड़ी चुनौती थी। चित्रजन लोकोमोटिव वर्क्स और सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जैसे संस्थान सिर्फ मैनुफैक्चरिंग इकाइयों के तौर पर नहीं, बल्कि तकनीकी क्षमता और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के संकल्प के प्रतीक के तौर पर स्थापित किए गए थे। डॉ. मुखर्जी के लिए, औद्योगीकरण कभी भी अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था; यह राष्ट्रीय क्षमता और सामूहिक आत्मविश्वास में किया गया एक निवेश था। हालांकि, किसी भी संस्थान के निर्माण के लिए केवल भौतिक अवसंरचना या प्रशासनिक कुशलता की ही जरूरत नहीं होती। इसके लिए सहानुभूति, जन-सेवा और नैतिक जिम्मेदारी की भावना की भी आवश्यकता होती है। डॉ. मुखर्जी में इन गुणों की झलक 1943 के बंगाल अकाल के दौरान ही साफ तौर पर दिखाई दी थी, जब उन्होंने बीसवीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य करने में खुद को समर्पित कर दिया था। विभाजन के बाद, उन्होंने स्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया।

स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन:विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति का व्यावहारिक रास्ता

ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता दृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थायित्व पर आधारित व्यावहारिक रास्तों को आगे बढ़ाने का अवसर देती है

श्री श्रीपाद नाइक

वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और जलवायु से जुड़ी गंभीर चुनौतियों के इस दौर में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी ऊर्जा प्रणालियों का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वच्छ व अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित, सस्ती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों तथा आर्थिक

आकांक्षाओं के अनुरूप भी हों। स्वच्छ ऊर्जा दरअसल ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और दीर्घकालिक विकास की दृष्टि से तेजी से अहम होती जा रही है। यह ईंधन बाजार में आने वाले उता-चढ़ाव से पैदा होने वाले जोखिमों को कम कर सकती है, ऊर्जा को अपेक्षाकृत अधिक सुलभ बना सकती है, रोजगार सृजित कर सकती है, घरेलू उद्योगों को मजबूत कर सकती है और देश को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ बना सकती है। फिर भी, स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के रास्ते एक जैसे नहीं हो सकते। इन रास्तों को राष्ट्रीय परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों और विकास की प्राथमिकताओं के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसी विंदु पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास के साझा लक्ष्यों को भी आगे बढ़ाया जा



सकता है। भारत का अपना अनुभव यह बताता है कि स्वच्छ ऊर्जा की शुरुआत लोगों से ही होनी चाहिए। पिछले दशक में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सीभाग) के तहत लगभग 28.6 मिलियन घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। इससे सभी तक बिजली पहुंचाने का काम आगे बढ़ा और ग्रामीण व कम सुविधा वाले इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमएवाई) के तहत महिलाओं को 105 मिलियन से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे खाना पकाने के साफ-सुथरे तरीकों को बढ़ावा मिला, घर में सेहत बेहतर हुई और कठिन श्रम का बोझ कम हुआ। ये पहल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करती हैं: स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को केवल स्थापित मेगावाट या जोड़ी गई क्षमता के आधार पर नहीं मापा जा सकता, बल्कि इससे पैदा हुए अवसरों, सुदृढ़ हुई आजीविका और बेहतर हुए जीवन स्तर के आधार पर भी मापा जाना चाहिए। लोगों को प्राथमिकता देने वाले इस दृष्टिकोण के साथ-साथ बड़े पैमाने पर काम और सहयोगी बुनियादी ढांचे की भी जरूरत है। भारत की स्वच्छ ऊर्जा की कहानी में नवीकरणीय ऊर्जा अहम हो गई है। लेकिन इसकी सफ़ाता इसे समर्थन प्रदान करने वाली प्रणालियों पर निर्भर करती है। सौर और पवन ऊर्जा को तेजी से अपनाना जा सकता है, लेकिन

इनकी पूरी क्षमता का लाभ तभी मिल पाएगा जब पारेषण (ट्रांसमिशन), वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन), भंडारण (स्टोरेज) और ग्रिड प्रबंधन एकसाथ मिलकर काम करें। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में सहायता प्रदान करने वाली प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। पारेषण संबंधी बुनियादी ढांचे (ट्रांसमिशन इंफ़्रस्ट्रक्चर) का निरंतर विस्तार हुआ है। इसके साथ-साथ ऊर्जा के भंडारण (एनर्जी स्टोरेज) और ग्रिड की सुदृढ़ता (ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी) के क्षेत्र में भी निवेश बढ़ा है। वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) संबंधी सुधारों और उन्नत ग्रिड तकनीक को अपनाने से एक ऐसी बेहतर एवं भरोसेमंद ऊर्जा प्रणाली बनाने में मदद मिली है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समन्वित करने में सक्षम है। भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन पर आधारित क्षमता अब 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं के अलावा, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) प्रणालियां डू जैसे कि रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, मिनी-ग्रिड और माइक्रो-ग्रिड डू ग्रामीण और कम सुविधा वाले इलाकों में स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक सुलभ बना रही हैं। ये प्रणालियां सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज, स्कूलों, हेल्थकेयर सेंटर्स तथा स्थानीय व्यवसायों को मदद पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण आजीविका और

मूल्य श्रृंखला का जुड़ाव: पीएम मित्र पार्क के ज़रिए कैसे भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र की बदल रही है तस्वीर

श्री पवित्रा मार्गिरटा

सदियों से, भारत की पहचान उसके परिधानों से गहराई से जुड़ी रही है। चाहे वह कश्मीर के पश्मीना की लंबे समय तक रहने वाली गर्माहट हो, अरब के मूंगा तिलक की सुनहरी चमक हो, तमिलनाडु की शाही कांजीवरम साड़ियाँ हों, चंदेरी की बुनाई हो या सूत के कारीगरों की कपड़ों पर मशहूर कारीगरी। आज भी यह क्षेत्र हमारी

अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा है, जो जीडीपी में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है। खेती के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यह क्षेत्र 45 मिलियन लोगों को सीधे तौर पर और 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। इससे ग्रामीण समुदायों को मजबूती मिलती है और देश भर में लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का रास्ता खुलता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के एक साथ जुड़ी हुई व्यवस्था के उलट, भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग जगहों पर फेले हुए मॉडल के तौर पर विकसित हुई। कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, कपड़े सिलाने और निर्यात जैसे गतिविधियाँ अलग-अलग राज्यों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुईं, जिसका अर्थ था कि एक कपड़ा बनने के दौरान अक्सर कई राज्यों की सीमाओं से गुज़रता था। इस बिखराव के कारण कई संरचनात्मक बाधाएँ पैदा हुईं। इसने बड़े पैमाने पर काम करने, आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन और आखिरकार मजदूरों की उत्पादकता को सीमित कर दिया इसके साथ ही, मल्टी-मॉडल संघर्ष में कमियों की वजह से लॉजिस्टिक्स का बोझ भी बढ़ जाता है। प्रोडक्शन के अलग-अलग चरणों के बीच हर बार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने या संभालने में अतिरिक्त खर्च और दुलाई का किराया लगता है। कई चरणों में लंबी दूरी तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से कुल लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और सामान को तेजी से बाजार तक पहुंचाने की क्षमता

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन : भारत के डिजिटल स्वास्थ्य का आधार

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में से एक का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत 104 करोड़ से ज्यादा स्वास्थ्य रिकॉर्ड 93 करोड़ से अधिक आभा खतों से जोड़े गए हैं। एबीडीएम ने कागजी कार्रवाई को खत्म कर और इंटरनेट के समय में कमी लाकर लोगों को बीमाकर्ताओं, अस्पतालों और डॉक्टरों से एक एकीकृत नेटवर्क से जोड़ दिया है। डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का

खत्म हो जाती है, जो आज की रिटेल व्यवस्था में बार-बार ऑर्डर देने वाले साइकल में एक बहुत बड़ी और नुकसानदायक कमी है। वर्तमान में पर्यावरण से जुड़ी जरूरतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वस्त्र उद्योग की हिस्सेदारी 8% से 10% और औद्योगिक जल प्रदूषण में 20% है। हजारों छोटी-छोटी और अलग-अलग जगहों पर फैली फैक्ट्री (कारखाना) को लागू करना और सही तरीके से प्रबंधन करना पहले एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती रहा है। इन रुकावटों को व्यवस्थित रूप से दूर करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) योजना शुरू की, जिसके लिए ₹4,445 करोड़ का बजट रखा गया। यह एक अहम कदम था, जो एक ऐसा व्यापक मॉडल पेश करता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों से जुड़े लोगों और निजी साझेदारों के साथ मिलकर विकास को आगे बढ़ाती है। इस योजना के केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी '5एफ' फ़र्मूला है यानी फ़र्म (खेत) से फ़ाइबर (रेशा) से फ़ैब्रिक (कारखाना) से फ़ैशन और फ़ैरने (विदेश) तक पहुंचें। यह सोच सीधे तौर पर उस बात को सामने लाती है, जो भारत को वैश्विक मंच पर अलग बनाती है: हमारी संपूर्ण और बेहद विविध मूल्य श्रृंखला। कच्चे माल के आयात या सिर्फ तैयार कपड़ों की बनावट पर निर्भर रहने वाले दूसरे देशों के उलट, भारत वस्त्रों को बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है, जिसमें किसानों के खेतों से लेकर हाई-फ़ैशन रनवे तक की प्रक्रिया शामिल है। इस अनोखी समझ की वजह से, हमारी विकास रणनीति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा और पूरी तरह से सामाजिक समानता के बीच एक खास संतुलन बनाने की जरूरत है। विस्तार करते समय, हमें हर क्षेत्र के कल्याण का ध्यान रखना होगा, ताकि साधारण किसान और ग्रामीण युवाक से लेकर कपड़े के निर्यातक तक, कोई भी पीछे न छूटे। पीएम मित्र फ़र्मवर्क इसी संतुलन को हासिल करता है। इन पार्कों को कच्चे माल के मुख्य केंद्रों के पास रणनीतिक रूप से बनाने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होता है और निर्माण के लिए बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इससे जरूरी बात यह है कि इस नज़दीकी से शुरुआत से

आखिर तक ट्रेकिंग भी मुमकिन हो पाती है। चूँकि वैश्विक ब्रांड ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रमाणिकरण की मांग करते हैं, इसलिए ये एकीकृत पार्क एक सत्यापन योग्य कस्टडी चीन देते हैं। इससे कड़े वैश्विक ईएसजी नियमों का पालन होता है और विदेशों में प्रीमियम कीमत पाने का रास्ता भी बनता है। 11,000 एकड़ से ज्यादा के एक ही इलाके में कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग और कपड़ा बनाने की सुविधाओं को एक साथ लाने से अलग-अलग राज्यों के बीच सामान ले जाने की जरूरत खत्म हो जाती है। इससे माल दुलाई का खर्च और ट्रांसपोर्ट से होने वाला प्रदूषण भी बहुत कम हो जाता है और सामान तेजी से बाजार तक पहुंच पाता है। सर्मापित माल गलियारों और एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर से जुड़े होने के कारण, विदेशी बाजारों तक सामान पहुंचाना बहुत सस्ता और किफ़ायती हो जाता है। हर पार्क में 'प्लग-एंड-प्ले' इंस्ट्रुक्शनल इंफ़्रस्ट्रक्चर होता है, जिसमें बिजली के खास सब-स्टेशन, लगातार पानी की सप्लाई और तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार फ़ैक्ट्री शेड जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके साथ ही, ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) तकनीक वाले उन्नत एडवांस्ड कॉमन एफ़्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और आधुनिक सुविधाएँ भी होती हैं, जिससे कारोबारियों पर ढ़ांचागत बोझ कम पड़ता है और कारोबार करने में आसानी होती है। पीएम मित्र पार्क तेजी से कागजी योजनाओं को असल ज़मीनी हकीकत में बदल रहे हैं। इस योजना में सात रणनीतिक पार्क शामिल हैं: पाँच ग्रीनफ़ैल्ड डेवलपमेंट किरधुनगर (तमिलनाडु), नवसारी (गुजरात), कलबुर्गी (कर्नाटक), धार (मध्य प्रदेश) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और दो ब्राउनफ़ैल्ड डेवलपमेंट वारंगल (तेलंगाना) और अमरावती (महाराष्ट्र) में। अब तक, इस योजना में कुल ₹69,899 करोड़ के निवेश की दिलचस्पी दिखाई गई है, जिसमें से ₹27,658 करोड़ का निवेश पहले ही हो चुका है। 10 मई, 2026 को माननीय प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के वारंगल में पहले कार्यरत पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क में पहले ही ₹3,862 करोड़ का निवेश हो चुका है और यहाँ विश्व-स्तरीय पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे पर काम किया जा रहा है। ये विशेषताएँ स्थायित्व के उन मानकों को दर्शाती हैं, जिन्हें सभी सात

स्थानीय आर्थिक सुदृढ़ता को भी बढ़ावा दे रही हैं। भारत की 'पीएम सूर्य घर': मुफ्त बिजली योजना' बड़े पैमाने पर इस दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस योजना से अब तक लगभग 4 मिलियन परिवारों को लाभ हुआ है, जिससे उपभोक्ता अपेक्षाकृत अधिक विकेंद्रीकृत एवं भागीदारी वाली ऊर्जा प्रणाली में योगदान देने वाले बन पाए हैं। हालांकि, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार में वित्त पोषण सबसे अहम तत्वों में से एक बना रहेगा। कई विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इन संभावनाओं को बड़े पैमाने पर लागू करने तथा बैंक से ऋण पाने योग्य परियोजनाओं में बदलने हेतु सस्ती और दीर्घकालिक पूंजी की जरूरत होती है। आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण संबंधी बुनियादी ढांचा, ग्रिड के आधुनिकीकरण, भंडारण प्रणाली और कम ऊर्जा खर्च करने वाली तकनीकों में निवेश बेहद जरूरी होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान वित्त पोषण, तकनीक संबंधी साझेदारी और क्षमता विकास के ज़रिए विकासशील देशों की मदद करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों के लिए सुदृढ़ एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुरक्षित, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा प्रणालियां सुनिश्चित करने हेतु मैनुफैक्चरिंग, तकनीक, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना जरूरी होगा। अब जबकि ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता आगे बढ़ रही है, सहयोग का एक ऐसी भविष्य-मुक्त रूपरेखा को मजबूत करने का अवसर है जो सामर्थ्य, बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता, विश्वसनीयता, तकनीक की सुलभता, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और सतत विकास का समर्थन करे।

चुनौती सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की ही नहीं, बल्कि ऐसे ऊर्जा प्रणाली के निर्माण की भी है जो सबके लिए सुलभ, किफ़ायती एवं भरोसेमंद होने के साथ-साथ दीर्घकालिक आर्थिक विकास और मानव विकास को कायम रखने में सक्षम हों।

पार्क साइटों पर स्थापित किया जा रहा है। पूरे देश में एक साथ काम शुरू होने से सहकारी संघवाद की तेजी और सफलता दोनों साफ़ दिखती हैं, जहाँ सभी सात राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, 100% ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी भी मिल गई है। पाँच ग्रीनफ़ैल्ड साइट्स के लिए जेवी एग्रीमेंट और एसपीवी पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। 2,158 एकड़ में फैले सबसे बड़े पार्क, धार (मध्य प्रदेश) में ₹21,436.9 करोड़ के निवेश में दिलचस्पी दिखाई गई है। इसी तरह गुजरात (₹13,084 करोड़), महाराष्ट्र (₹12,925 करोड़), तमिलनाडु (₹26,600 करोड़), उत्तर प्रदेश (₹5,345.8 करोड़) और कर्नाटक (₹1,700 करोड़) में भी काम को लेकर तेजी देखी गई है। तेजी से हो रहे इस काम के पीछे केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिजा सिंह का सक्रिय नेतृत्व है। उनके कुशल नेतृत्व में वस्त्र मंत्रालय अपने कामकाज के तरीकों में तेजी लाया है, मंत्रालय ने प्रशासनिक रुकावटों को दूर किया है और राज्य सरकारों के साथ अभूतपूर्व स्तर पर आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है। लेकिन आंकड़े तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली पैमाना इसके मानवीय प्रभाव में दिखता है। प्रत्येक पार्क को संरचनात्मक रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यानी सभी सात स्थलों को मिलाकर, 21 लाख से अधिक औपचारिक आजीविकाएँ हैं, जो हमारे ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को अहम सामाजिक-आर्थिक नींव प्रदान करती हैं, जो पारंपरिक रूप से परिधान निर्माण उद्योग की रीढ़ हैं। यह व्यापक ढांचागत प्रयास वस्त्र क्षेत्र के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण 2030 के लिए एक अहम लॉन्चपैड का काम करता है, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक भारत के वस्त्र उद्योग को 350 मिलियन डॉलर तक और अत्यधिक मशीन में बदलना है। ऐतिहासिक विखंडन को विश्व स्तरीय, एकीकृत पैमाने से बदलकर करके, पीएम मित्र एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन ला रहा है। सशक्त नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हम भारत को वस्त्रों के निर्विवाद, टिकाऊ और अत्यधिक प्रतियोगी केंद्र के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। (लेखक केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं। व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं।)

विकसित स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ता है। यह मजबूत करने के लिए सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की शुरुआत की। एक एबीडीएम-सक्षम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) से जुड़े डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा, वे मरीज की सहमति लेने के बाद उनके पिछले रिकॉर्ड के डिजिटल रूप से देख सकते हैं और मरीज की ऐसी मंजूरी, जिसे कभी भी वापस लिया जा सके और जो एक तय समय के लिए हो, के ज़रिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का आदान-प्रदान कर सकते हैं। आभा आधार की तरह एक विशिष्ट पहचान है, जो लोगों को सुरक्षित रूप से व्यापक

मुनि संधान सागर जी महाराज के सान्निध्य में चढ़ाया निर्वाण लाडू

शिखर जी (विश्व परिवार)। संत शिरोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक-तपस्वी शिष्य, युवा तरुणाई के प्रखर वक्ता मुनि श्री 108 संधानसागर जी महाराज के मंगल सान्निध्य में आज 13 वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर तीर्थराज सम्पदशिखर जी की सुवीर टोंक पर श्रावको ने पूर्ण भाक्ति भाव के साथ निर्वाण लाडू चढ़ाया। परमपूज्य मुनिवर की आज 21वीं वंदना थी। उन्होंने चोपड़ा कुण्ड एवं पार्श्वनाथ पर अभिषेक शान्तिधारा कराने के बाद विमलनाथ भगवान की टोंक पर भी चरणों का अभिषेक एवं मंत्रोच्चारण से शान्तिधारा करवाई। शान्तिधारा का सौभाग्य अरिजय जैन-नौएडा-दिल्ली ने तथा निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य कोलकत्ता के श्री विमल जी जैन ने प्राप्त किया। निर्वाण काण्ड पढ़ते हुये पूज्य



युनिवर के सान्निध्य में भक्तों ने टोंक पर निर्वाण गुणायतन लाडू समर्पित किया। महाराज श्री प्रातः 4.40 पर गुणायतन से गये और पुरी वंदना कर 9.30 पर नीचे लौट आये। मुनि श्री का 4.30-5 घंटे में पूर्ण वंदना कर नीचे आना सभी भक्तों श्रावको के लिए विस्मय का विषय बना हुआ है। इससे पूर्व मुनिवर ने गिराराज पर 36 घंटे का ध्यान लगाया ओ दो वंदना कर नीचे आये ये भी विशेष बात है कि मुनि श्री चातुर्मास में पहाड़ पर नहीं जायेंगे। अतः अष्टाहिनिका पूर्व ही 27 वंदना पूरी करेंगे। वे पहाड़ पर कभी आहार नहीं लेते न ही निहार आदि करते हैं ये पवित्र एवं पूज्य पहाड़ है यहाँ तक कि वे अपना कमण्डल सदैव नीचे गुणायतन में ही छोड़कर जाते हैं ताकि कोई विकल्प ही नहीं रहे। धन्य है ऐसे गुरुदेव की साधना। श्रावको ने सान्निध्य पा अपने को कृतार्थ दिया।

कुण्डलपुर में भगवान श्री विमलनाथ जी के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया

कुण्डलपुर दमोह (विश्व परिवार)। सुप्रसिद्ध सिद्धेश्वर कुण्डलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समयसागर जी महाराज के आशीर्वाद से आर्थिकार रत्न श्री चिंतनमति माताजी ससंघ के सान्निध्य में जैनधर्म के तेरहवें तीर्थंकर भगवान श्री विमलनाथ जी का मोक्षकल्याणक महोत्सव 8जुलाई 2026 को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः भक्तमर महामंडल विधान, पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक, शान्तिधारा, ऋद्धि कलश, पूजन, विधान हुआ। अत्यंत भक्ति भावपूर्वक निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। प्रचार मंत्री जयकुमार जलज ने बताया कि



इस अवसर पर प्रथम अभिषेक, ऋद्धि कलश, शान्तिधारा आदि करने का सौभाग्य श्रेष्ठी श्री रमेश चंद्र कपिल अहम चंपावत इंदौर, शुभम सुनील प्राची सुनीला

डबुल्या परिवार बांदकपुर, प्रवीण जैन महावीर ट्रांसपोर्ट दमोह, राकेश सूर्याश अभिषेक जैन आगरा, रजत अखिल सक्षम सचिन जैन रायपुर, आशा देवी दीपशिखा अंश लोकेश सिंघई परिवार ललितपुर, स्वरूप प्रकाशचंद पिण्डारमेया नांगामा, प्रकाशचंद प्रबल जैन महेवा, मानिकचंद चैना मनीष सपना परिवार जबलपुर, सुनील आर्यन गुना, पारस गांधी अहमदाबाद, अभिनव प्रदीप दिवाकर सागर, प्रमोद पारुल प्रांजल जैन परिवार लखनादीन आदि के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सौभाग्य प्राप्त किया। सायंकाल भक्तमर दीप अर्चना एवं पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती हुई।

निगम ने अभियान चलाकर पुजारी पार्क टिकरापारा मुख्य मार्ग से अवैध कब्जे हटाया



रायपुर (विश्व परिवार)। आज टीम प्रहरी अभियान अंतर्गत रायपुर पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम आयुक्त श्री संवित मिश्रा के निदेशानुसार नगर निगम जोन 6 क्षेत्र में नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड्डादस्ता और नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग द्वारा यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता श्री आशीष

श्रीवास्तव, उपअभियंता श्री सागर ठाकुर की उपस्थिति में नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग ने टिकरापारा पुजारी पार्क के पास मुख्य मार्ग में अभियान चलाकर वहां से लगभग 6 टेलो को हटाने एवं मार्ग को कब्जा मुक्त करने कार्यवाही की और लगभग 13 दुकानदारों को भविष्य के लिए कड़ई कार्रवाई की चेतावनी देते हुए निर्देशानुसार नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग द्वारा यातायात पुलिस बल की उपस्थिति में जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव मार्गनिर्देशन और कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता श्री आशीष

मुनि श्री ने किया दर्शनोदय तीर्थ थूवोनजी के लिए प्रस्थान

■ मुनि संघ के साथ मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है : विजय धुरा

अशोक नगर (विश्व परिवार)। परम पूज्य आचार्य आर्जव सागर महाराज जी के शिष्य मुनि श्री विशोभ सागर जी मुनिराज के शम को दर्शनोदय तीर्थ थूवोनजी के लिए पद विहार कर दिया पूज्य श्री को मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज जैन समाज अध्यक्ष राकेश कांसल महामंत्री राकेश अमरोद मंत्री विजय धुरा मंत्री शैलेन्द्र श्रागर संयोजक उमेश सिंघई मनीष सिंघई सहित अन्य प्रमुख जनों ने भाव भरी विदाई देते हुए बगीचे मंदिर से पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचे यहाँ युगल मुनि राज ने वंदना कर आगे के लिए पद विहार कर दिया।



आदीश्वर धाम सुभाषगंज में बुधवार को दोपहर 4 वजे धर्म सभा को सम्बोधित करते हुए मुनि श्री विशोभ सागर जी महाराज ने कहा कि जीवन में पसीना बहाने वाले पानी से नहाने हैं और संयम के मार्ग पर पसीना बहाने वाले अपना इतिहास बदलते चले जाते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने वाले को आप सेवा करने वाले भी सिद्धालय तक कि यात्रा करते

जन्ता अभिषेक शान्ति धारा के साथ महा मंडल विधान का लाभ लेना चाहते हैं तब समय जनों से गलती होना स्वाभाविक है अल्प प्रवास पर भी समाज ने संत समागम का भरपूर लाभ लिया है इस दौरान भक्तों को परम पूज्य सभी तरह का लाभ मिल रहा है परम पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज की मंगल देशना प्रतिदिन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस दौरान आचार्य श्री विद्यासागर सर्वोदय पाठशाला शान्ति नगर की बहनों को परम पूज्य मुनि संघ के सान्निध्य में पुरस्कृत किया गया।

संत हमेशा सावधान रहते हुए अपनी चर्या का पालन करते हैं: मुनि श्री

इस दौरान गंज मन्दिर विराजमान मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज ने कहा कि संत हमेशा सावधान रहते हैं वे दस प्रकार के दोषों को टाल कर अपनी चर्या को कठोरता पालन करते हैं श्रमण प्रतिपल अपने कर्मों से सावधान रखते हुए आगे बढ़ते हैं परम पूज्य मुनिश्री विशोभ सागर जी महाराज के साथ हम लोग झारखंड में साथ रहे।

जी.आर. मरकाम ने निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण किया



राजनांदावां (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम के नवागत आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम ने आज अपराह्न में पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग,महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र. ई.एस.डी.बी. 102(1) /414/2026-जी.ए.डी.-4 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07 जुलाई

2026 द्वारा श्री जी.आर. मरकाम (राप्रसे, आर.आर.-2014) अपर कलेक्टर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को आयुक्त,नगर पालिक निगम राजनांदावां के पद पर पदस्थ किया गया है। श्री मरकाम ने आज अपराह्न में नगर निगम कार्यालय पहुंच कर पदभार ग्रहण किया एवं नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया।

कृषि महाविद्यालय भाटापारा में मनाया गया वृक्षारोपण सप्ताह

■ नीम, कटहल सहित 150 से अधिक लगाये गए पौधे



बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। दाऊ कल्याण सिंह कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, भाटापारा में अतिथि डा. एच. एल. सोनबोरडे के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सेवा योजना सामान्य इकाई द्वारा 1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक महाविद्यालय में वृक्षारोपण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विभिन्न चर्यानि क्षेत्रों में स्वयंसेवकों, छात्रों, समस्त प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया गया।

150 पौधे लगाये गए हैं इसके अलावा कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते एक पेड़ माँ के नाम पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ,हरियाली ही खुशहाली जैसे प्रेरणादायी नारों के माध्यम से वृक्षारोपण जागरूकता अभियान चलाया गया। अंतिम दिवस 7 जुलाई को कुल 55 पौधों रोपित किये गए तथा छात्रों ने वृक्षारोपण विषय पर पोस्टर बनाए। कार्यक्रम के समापन में वरिष्ठ प्राध्यापक एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अंगद सिंह राजपूत ने छात्रों को वृक्षारोपण एवं पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि वृक्ष हमें प्राण वायु प्रदान करने के साथ साथ मृदा एवं जल संरक्षण, जैव विविधता तथा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं छात्रों ने विद्यार्थियों को पेड़ लगाने के हित साक्षित न रहकर उचित संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जिम्मेदार बनने तथा जीवन में अपने आस पास के खुले स्थानों में अधिक से अधिक पर पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया।

कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में अनूठी पहल मुनगा पौधारोपण से घर-घर पहुंचेगा पोषण का संदेश

रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संवर्धन को जनआंदोलन बनाने के लिए लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के आह्वान पर प्रदेशभर में कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में बेंटी बचाओडूबेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजित 'मुनगा पौधारोपण विथ सेल्फे अभियान' ने पोषण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का प्रभावी संदेश दिया।

बेमेतरा जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), सेक्टर दाढ़ी-2 एवं सेक्टर कन्हेरा में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गंधीर कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा एनीमिक महिलाओं के 18 घरों में मुनगा के पौधे रोपे गए और परिवारों को पौधों की देखभाल एवं नियमित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। मुनगा (सहजान) को 'सुर पृष्ठ' के रूप में जाना जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों और फूलों में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी तथा अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

पहले सुरक्षा का इतिजाम करें, फिर पौधरोपण का काम करें : महेन्द्र

■ शिक्षक महेन्द्र हर साल जन्मदिन पर लगाते हैं 100 पौधे



आरंग (विश्व परिवार)। चरौदा में पदस्थ शिक्षक महेन्द्र कुमार पील ने प्रकृति संरक्षण को अपने जीवन का ध्येय बना लिया है। पर्यावरण के प्रति उनका समर्पण इस कदर है कि उन्होंने अपने मरणोपरान्त भी पौधरोपण अभियान जारी रखने के लिए 50 हजार रुपए से अधिक की राशि बैंक में डिपॉजिट करने का संकल्प रखा है, ताकि उनके जाने के बाद भी उनके नाम से पौधे लगाए जा सकें। शिक्षक महेन्द्र पटेल द्वारा अपने गृहग्राम लालिन कला, वर्तमान निवास आरंग और पदस्थापना स्थल चरौदा में लगाए गए करीब 300 पौधे आज वृक्ष बनकर फल

इसके अलावा, समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने 'पेंड बर झगरा' नामक एक लघु फिल्म (शॉर्ट फिल्म) भी बनाई है, जो लोगों को प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देती है। शिक्षक महेन्द्र हर साल 9 जुलाई को अपने जन्मदिन पर 100 पौधे लगाने का संकल्प लेते हैं। वे गांव के मृत बुजुर्गों की स्मृति में पीपल, बरगद, नीम और कदम जैसे दीर्घायु वृक्ष लगाते हैं। पर्यावरण को समर्पित अपनी संस्था 'पीपला फाउंडेशन' के माध्यम से वे हर वर्ष सैकड़ों पौधों का दान करते हैं और लोगों को प्रकृति को संवराने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वह कहते हैं पहले सुरक्षा का इतिजाम करें फिर पौधरोपण का काम करें। उन्होंने पौधरोपण के बाद उनकी सुरक्षा पर विशेष जोर देने अपील किए हैं।

जिला खनिज संस्थान न्यास निधि से कोरबा में सिपेट केन्द्र की स्थापना

कोरबा (विश्व परिवार)। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिपेट (पूर्व में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) रसायन और पेट्रोकैमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्लास्टिक्स एवं पालमर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है जो कि शैक्षणिक (Academics), कौशल विकास (Skill Development), प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं (Technical Support Services) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाओं के लिए पूरी तरह से विकसित एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। सिपेट भारत सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से पेट्रोकैमिकल्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उद्योगों को तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु कोरबा शहर के क्षेत्र एजुकेशन हब, स्याहीमुडी, ब्लॉक कटघोरा, पोस्ट-

कटघोरा, कोरबा-495445, छत्तीसगढ़ में एक नया विस्तार केंद्र सितम्बर 2018 में स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरबा शहर में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) निधि कोरबा के माध्यम से सिपेट केन्द्र की स्थापना हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय एकीकृत शैक्षणिक परिसर, एजुकेशन हब, स्याहीमुडी, जमनोपाली, कोरबा में कुल 18.20 एकड़ भूमि व निर्मित भवन के साथ साथ संयंत्र एवं तकनीकी बुनियादी ढांचे मशीनरी, लैब उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, फर्नीचर और फर्निशिंग आदि के निर्माण के लिए तथा परियोजना अवधि के दौरान संस्थान के आवर्ती व्यय हेतु 25 करोड़ राशि दिया गया। सिपेट को भवन सौंपने और अधिग्रहण के बाद परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रम और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई।

मोदी की गारंटी और साय सरकार की शिक्षा व्यवस्था दोनों कागजों तक सीमित : वन्दना राजपूत

■ बच्चे आज भी शिक्षक किताब और यूनिफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं



रायपुर (विश्व परिवार)। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वन्दना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह भगवान भरोसे छोड़ चुकी है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन देश के हजारों सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अब तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफॉर्म तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यह सरकार की प्रशासनिक विफलता और शिक्षा के प्रति उदासीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा उदाहरण बेमेतरा जिला में देखने को मिल रहा है वहाँ एक भी स्कूल में बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं ऐसे में बच्चे कैसे समय पर कोर्स कम्प्लीट कर पाएंगे इधर शिक्षा मंत्री हर रोज एक नया नियम लाते हैं और यह सिर्फ कागजों तक ही सिमटकर रह जाता है। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित होती जा रही है

भाजपा सरकार से अभिभावक सवाल पूछ रहे हैं कि जब स्कूल खुलने की तारीख पहले से तय थी, तब किताबों और यूनिफॉर्म की व्यवस्था समय पर क्यों नहीं की गई? क्या शिक्षा विभाग पूरी तरह विफल हो चुका है? इस लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार बच्चों के भविष्य को भी फइलों और बैठकों में उलझाकर रखना चाहती है? कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वन्दना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता शिक्षा नहीं, केवल प्रचार ही है। यदि सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर होती तो आज प्रदेश का कोई भी बच्चा बिना किताब और यूनिफॉर्म के स्कूल जाने को मजबूर नहीं होता भाजपा सरकार ने बच्चों को समय पर किताबें और यूनिफॉर्म तक नहीं दे पा रही है वह नई शिक्षा व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करने का नैतिक अधिकार नहीं है बच्चों का भविष्य किसी भी सरकार की कसबे बिना यूनिफॉर्म के स्कूल जाने को मजबूर नहीं है। सरकार के दावे और धरातल की हकीकत में बड़ा अंतर है।

तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने पुरंदर मिश्रा से की सौजन्य भेंट



रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, जिला शाखा रायपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा से सौजन्य भेंट की। इस दौरान संघ ने कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों एवं ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के संबंध में विधायक को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हुए उनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया। विधायक पुरंदर मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता

से सुना तथा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित स्तर पर आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान जनहित एवं कर्मचारी हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई। विधायक श्री मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा तथा जनसेवा और संवाद की परंपरा निरंतर जारी रहेगी। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सहयोग एवं सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की।

दैनिक विश्व परिवार

संक्षिप्त समाचार

उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर सभी संभागीय एवं जिला मुख्यालयों में लगेगी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा, 10.60 करोड़ रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सांसद महेश कश्यप एवं महापौर संजय पांडे के प्रति आभार -- संग्राम सिंह राणा सभापति राजस्व



जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी संभागीय एवं जिला मुख्यालय वाले नगरीय निकायों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भव्य प्रतिमाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन तथा उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव की पहल पर राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 10 करोड़ 60 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। देश के प्रथम उद्योग मंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद् एवं राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य के 32 नगरीय निकायों में उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए राशि स्वीकृत की गई है। नगर निगम जगदलपुर के राजस्व सभापति संग्राम सिंह राणा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, बस्तर सांसद महेश कश्यप तथा जगदलपुर महापौर संजय पांडे के प्रति आभार व्यक्त किया है। संग्राम सिंह राणा ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी समाज और विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में उनकी प्रतिमा स्थापित होने से नागरिकों, विशेषकर युवाओं को उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं राष्ट्रसेवा के आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त होगी।

बोधघाट थाना बना छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना



जगदलपुर। बस्तर पुलिस के लिए गर्व की बात है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 की वार्षिक पुलिस थाना रैंकिंग में बोधघाट थाना को छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया है। यह पहली बार है जब बस्तर क्षेत्र के किसी थाना को यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यह सम्मान अपराध नियंत्रण, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान, सामुदायिक पुलिसिंग, जनसहभागिता, नागरिक-अनुकूल पुलिसिंग एवं उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के आधार पर प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक लीलाधर राठौड़ एवं वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक तामेश्वर चौहान को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। बस्तर पुलिस ने इस उपलब्धि का श्रेय थाना के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम भावना, समर्पण और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को दिया है।

वर्षों से कार्यालयों में जमे 17 शिक्षक-कर्मचारी लौटे मूल पदस्थापना पर, लेकिन अधूरी कार्रवाई पर उठे सवाल

गरियाबंद (विश्व परिवार)। जिले के शिक्षा विभाग में वर्षों से विभिन्न कार्यालयों में संलग्न रहकर गैर-शिक्षकीय कार्य कर रहे शिक्षकों एवं कर्मचारियों को आखिरकार उनके मूल पदस्थापना स्थल पर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार चंद्राकर ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए 17 शिक्षक एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय एवं कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर दिया।

यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा 25 जून 2026 को जारी निर्देशों तथा 23 जून को स्कूल शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन में की गई है। आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बीआरसी कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालयों में वर्षों से संलग्न शिक्षकों एवं कर्मचारियों को तत्काल उनकी मूल पदस्थ संस्था में भेजा जाएगा।

जानकारी के अनुसार जिले के कई शिक्षक एवं कर्मचारी लंबे समय से शिक्षण कार्य छोड़कर कार्यालयों में प्रशासनिक दायित्व निभा रहे थे। दूसरी ओर अनेक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई थी,

जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। ऐसे में विभाग की इस कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, समग्र शिक्षा कार्यालय, विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसी) कार्यालय गरियाबंद, मिश्र, मैनुपुर एवं देवभोग सहित विभिन्न कार्यालयों से संलग्न कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थ संस्थानों के लिए कार्यमुक्त किया गया है।

स्पर्ध किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा संबंधित सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को उनकी मूल संस्था अथवा कार्यालय के लिए कार्यमुक्त माना जाएगा।

लेकिन कार्रवाई पर उठने लगे बड़े सवाल

क्या केवल 17 कर्मचारियों तक सीमित रहेगा आदेश?

विभागीय आदेश के बाद अब इसकी निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि यह कार्रवाई अभी अधूरी और चुनिंदा लोगों तक सीमित दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में आज भी ऐसे कई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर के आदेश से विभाग में पदस्थ किया गया था। इनमें कुछ कर्मचारियों का वेतन प्रतिनियुक्ति की तर्ज पर सीधे शिक्षा विभाग से आहरित हो रहा है, जबकि कुछ का वेतन अब भी विकासखंड छुपा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल से निकाला जा रहा है।

इससे प्रधान पाठक, एलबी शिक्षक, सहायक ग्रेड-02 तथा सहायक ग्रेड-03 सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत कुल 17 अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षकों की मूल विद्यालयों में वापसी से लंबे समय से शिक्षक विहीन या शिक्षक कमी से जूझ रहे विद्यालयों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे विद्यार्थियों को नियमित शिक्षण उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में

कर्मचारियों को भी शासन के निर्देशों के अनुरूप मूल पदस्थापना पर भेजा जाएगा, या कार्रवाई केवल कुछ कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी?

कस्तूरबा विद्यालयों की पदस्थापना भी चर्चा में

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, गरियाबंद में पदस्थ एक शिक्षिका तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, देवभोग में पदस्थ एक प्रभारित शिक्षिका का मूल विद्यालय विकासखंड मैनुपुर बताया जा रहा है। ऐसे में इन मामलों में भी शासन के नियमों और आदेशों का समान रूप से पालन होना या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।

शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई ने वर्षों से चली आ रही संलग्नीकरण व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब यह देखा होगा कि नियम सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं या फिर कार्रवाई चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जाती है। आने वाले दिनों में विभाग की आगामी कार्रवाई इस पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट करेगी।

1 फिटल से ज्यादा गांजा के साथ मध्यप्रदेश के दो तस्कर गिरफ्तार, 55 लाख की जब्ती

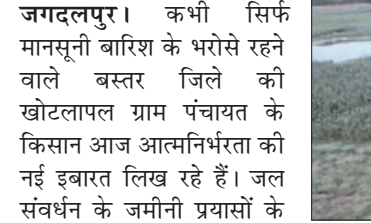


मिली कि एक सफेद रंग की डस्टर कार में भारी मात्रा में अवैध गांजा लेकर तस्कर देवभोग रोड से मैनुपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने झरियाबहरा तिराहा के पास बैरिकेडिंग कर वाहनों को जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार सफेद डस्टर कार दिखाई दी। पुलिस ने वाहन रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार से भागने लगा। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वाहन को घेरते हुए रोक लिया। पूछताछ में वाहन सवारों ने अपना नाम आर्यन मालवीय (20 वर्ष) और अभिषेक महेशकर (23 वर्ष), दोनों निवासी इछावर, जिला सीहोर (मध्यप्रदेश)

बताया। गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी लेने पर उसमें 102.750 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 51.37 लाख रुपये आंकी गई। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त डस्टर कार (क्रमांक सीसी-04-केडब्ल्यू-5689) कीमत 3.50 लाख रुपये तथा दो मोबाइल फोन कीमत 11,500 रुपये भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 54.99 लाख रुपये है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना मैनुपुर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बताया। गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी लेने पर उसमें 102.750 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 51.37 लाख रुपये आंकी गई। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त डस्टर कार (क्रमांक सीसी-04-केडब्ल्यू-5689) कीमत 3.50 लाख रुपये तथा दो मोबाइल फोन कीमत 11,500 रुपये भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 54.99 लाख रुपये है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरी कार्रवाई में थाना मैनुपुर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

खोटलापल ग्राम पंचायत में डबरी निर्माण से बदली ग्रामीणों की तकदीर, किसानों की आय में होगी वृद्धि



जगदलपुर। कभी सिर्फ मानसूनी बारिश के भरोसे रहने वाले बस्तर जिले की खोटलापल ग्राम पंचायत के किसान आज आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहे हैं। जल संवर्धन के जमीनी प्रयासों के तहत गाँव में निर्मित एक डबरी (छोटे तालाब) ने न केवल क्षेत्र के भूजल स्तर को सुधारा है, बल्कि परंपरागत खेती से आगे बढ़कर रबी फसल और मत्स्य पालन के जरिए स्थानीय किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त बना दिया है। महात्मा गांधी नरेगा और जल संवर्धन योजनाओं के तहत हितग्राही सोनधर और मोंगर के खेतों में निर्मित इस डबरी ने सिंचाई के संकट को दूर करने के साथ-साथ



ग्रामीणों के जीवन में एक क्रांतिकारी और सकारात्मक बदलाव की नींव रखी है। इस जल संरचना के निर्माण से खुश होकर ग्रामीण सोनधर कहते हैं कि यह डबरी जल संकट के स्थायी समाधान के रूप में सहायक होगा, क्योंकि अब इसमें बारिश का पानी एकत्रित होने से सिंचाई के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और डबरी ने सिंचाई के संकट को खतरे से पूरी तरह बचाया जा

सकेगा। वहीं अब डबरी में पर्याप्त पानी जमा होने से वे रबी सीजन में दूसरी फसलों के साथ-साथ उन्नत साग-भाजी का उत्पादन भी कर पाएंगे जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। खेती में आए इस सुधार के दौरान ग्राम पंचायत के दर्जनों स्थानीय जाँवकाईधारी ग्रामीण मजदूरों को सीधे उनके अपने गाँव में ही रोजगार मिला, जिसने क्षेत्र से होने वाले पलायन पर एक प्रभावी रोक लगाने का काम किया है।

घने जंगलों के बीच रोशनी की दस्तक: कार्लाकोटा में पहली बार जले बिजली के बल्ब

सघन वन क्षेत्र के 43 परिवारों तक पहुंची बिजली, विकास की नई किरण

करीब एक करोड़ की लागत से पूरा हुआ विद्युतीकरण कार्य, एससीए योजना से मिली सौगात

जगदलपुर। विकासखंड लोहंडीगुड़ा के सघन वनों से घिरे ग्राम कार्लाकोटा में अब अंधेरा बीते दिनों की बात हो गई है। वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे इस दूरस्थ आदिवासी गाँव में विद्युतीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पहल से गरीबी रेखा वर्ग के 43 परिवारों के घरों में पहली बार बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीणों के जीवन में विकास और उम्मीद की नई रोशनी आई

है। ग्रामीणों ने अपने गाँव में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आवेदन दिया था। जिला के आला अधिकारी ने भी गाँव का दौरा कर ग्रामीणों से चर्चा की थी और ग्रामीणों को विकास कार्यों के लिए आश्वस्त भी किया था। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और घने जंगलों के बीच विद्युत अधोसंरचना तैयार करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विभाग ने इसे सफलतापूर्वक पूरा कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। इस परियोजना के तहत 3 किलोमीटर 11 केवी विद्युत लाइन, 4.9 किलोमीटर लो टेंशन (एलटी) लाइन तथा 25 केवी क्षमता के चार ट्रांसफॉर्मर स्थापित किए गए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य पर 99.19 लाख रुपये की लागत आई है, जिसका भुगतान एससीए (स्वच्छदुग्ध श्रद्धाह्वय) योजना के

अंतर्गत किया गया है। योजना का उद्देश्य दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

बिजली पहुंचने से अब ग्रामीणों को रात में रोशनी, बच्चों को बेहतर अध्ययन का माहौल, घरेलू कार्यों में सुविधा तथा भविष्य में विभिन्न आजीविका गतिविधियों के नए अवसर मिल सकेंगे। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी सेवाओं तक पहुंच भी पहले की तुलना में अधिक आसान होगी। कार्लाकोटा में विद्युतीकरण केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि यह दूरस्थ वनांचल में विकास की नई शुरुआत का प्रतीक है। यह पहल दर्शाती है कि शासन की योजनाएं अब अंतिम छोर पर बसे परिवारों तक भी प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

बारिश ने खोली बدهाल व्यवस्था की पोल: कोपरा शासकीय स्कूल परिसर बना तालाब, बच्चों की सुरक्षा पर मंडराया खतरा

गरियाबंद (विश्व परिवार)। जिले में लगातार हो रही बारिश ने कोपरा के शासकीय विद्यालय की बدهाल व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। विद्यालय का पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। जगह-जगह पानी भर जाने से खेल मैदान तालाब में तब्दील हो गया है, जबकि मैदान में उगी घनी घास के कारण जहरीले सांप और बिच्छुओं का खतरा बढ़ गया है। इस स्थिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के बाद कई दिनों से स्कूल परिसर में पानी जमा रहने के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छोटे-छोटे बच्चे पानी से होकर कक्षाओं तक पहुंचने को मजबूर हैं। इससे दुर्घटना और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। विद्यालय के खेल मैदान में लंबे



समय से साफ-सफाई नहीं होने के कारण घास तेजी से फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में जहरीले सांप और बिच्छू आसानी से छिपे रहते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते मैदान की सफाई और घास की कटाई नहीं कराई

गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन समिति और नगर पंचायत को कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से यही स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग स्थायी समाधान की दिशा में

कोई ठोस कदम नहीं उठाते। पालकों ने विद्यालय परिसर से तत्काल पानी निकासी, मैदान की साफ-सफाई, घास कटाई और नियमित रखरखाव की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन संबंधित विभाग लापरवाही बरत रहे हैं।



स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन किया जाएगा। साथ ही जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर विद्यालय परिसर का निरीक्षण कराने और जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की मांग की गई है।

शाला विकास समिति के अध्यक्ष दिनेश साहू ने बताया कि विद्यालय में पानी निकासी की समस्या के समाधान के लिए प्रयास जारी हैं। जल्द ही आवश्यक व्यवस्था कर समस्या का निराकरण किया जाएगा। वहीं विकासखंड शिक्षा अधिकारी

मिथेश्वर हेमंत साहू ने कहा कि मामला गंभीर है। कोपरा स्कूल का चयन स्वामी विवेकानंद स्कूल के रूप में हो चुका है। मैदान समतलीकरण एवं अन्य विकास कार्यों के लिए शासन को 33 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह ने भारतीय आयुर्वेद संस्थान में भावी स्वास्थ्य पेशेवरों को किया प्रेरित

रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन, पेशेवर उत्कृष्टता और आधुनिक तकनीकी क्षमता को रेखांकित करते हुए एम्स रायपुर में 'ऑपरेशन सिंदूर' विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। यह व्याख्यान ब्रिगेडियर तेजिंदर सिंह बाबा, सेना मेडल, कर्मांडर, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा सब एरिया द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों, संकाय सदस्यों, मेडिकल एवं नर्सिंग विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स तथा पूर्व सैनिकों ने भाग लिया और भारतीय सेना के एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान की योजना, क्रियान्वयन और महत्व को समझने का अवसर प्राप्त किया।



अपने प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक संबोधन में ब्रिगेडियर बाबा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनाई गई रणनीति, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सूक्ष्म योजना,

उत्कृष्ट समन्वय, अदम्य साहस और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग से इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने लंबे सैन्य अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय में युद्ध केवल रणभूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए सटीक

रणनीति, तकनीकी श्रेष्ठता, खुफिया जानकारी और मजबूत टीमवर्क की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं तथा आधुनिक तकनीकों, उन्नत हथियार प्रणालियों और कठोर प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी क्षमताओं को लगातार सशक्त बना रहे हैं। ब्रिगेडियर बाबा ने अपने सैन्य जीवन के कई प्रेरक अनुभव भी साझा किए। उन्होंने अनुशासन, ईमानदारी, निःस्वार्थ सेवा, कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण जैसे मूल्यों पर विशेष बल दिया। उन्होंने मेडिकल एवं नर्सिंग के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे

अपने पेशेवर जीवन में भी इन मूल्यों को अपनाएँ। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी समर्पण, टीमवर्क और राष्ट्रसेवा की भावना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सेना में। इस व्याख्यान में संस्थान के वरिष्ठ संकाय सदस्य, चिकित्सक, नर्सिंग अधिकारी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स तथा पूर्व सैनिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह कार्यक्रम भावी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित अधिकारी से सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हुआ। साथ ही इसने प्रतिभागियों में साहस, समर्पण, टीमवर्क और राष्ट्रसेवा जैसे मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करने का संदेश दिया।

कूड आयल के दाम घटे, पेट्रोल डीजल के दाम में कमी नहीं : कांग्रेस

रायपुर (विश्व परिवार)। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो गये मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल के दाम नहीं घटा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कूड ऑयल की कीमतों में 56 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है जो कूड ऑयल के दाम 157 डॉलर प्रति बैरल के उच्चे स्तर तक था, आज 70 डॉलर है इसमें प्रति बैरल लगभग 87 डॉलर की कमी हुई, लेकिन देश के भीतर किसान मजदूर युवा व्यापारी उद्योगपतियों को आज भी महंगे दरों पर पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ रहा है। मोदी सरकार, साय सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों मिलकर आम जनता की जेब से पेट्रोल डीजल के माध्यम से प्रति लीटर 48 से 52 रूप से अधिक की कमाई कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग



अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पिछले 15 दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 56 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, इसका लाभ उपभोक्ताओं को देने के बजाए यह सरकार अपने मुनाफे में एडजस्ट कर रही है। यह देश की गरीब जनता पर अत्याचार है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए केंद्र की मोदी सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफखोरी गठबंधन को

जिम्मेदार है। पश्चिम एशिया तनाव शुरू होने से पहले कूड आयल के जो दाम थे, आज उससे भी कम हो गये हैं। जब कूड ऑयल थोड़ा महंगा हुआ तो मोदी सरकार ने 10 दिनों के भीतर डीजल-पेट्रोल के दाम 6-6 बार दाम बढ़ाये, अब कूड आयल के दाम गिरने पर भी लूट जारी है। मोदी की गारंटी पेट्रोलियम कंपनियों की मुनाफ बढ़ाने की है और आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आज देश के सामने मोदी सरकार की मुनाफखोरी उजागर हो गई है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है तो पेट्रोल डीजल के दामों में उसी के मुकाबले कमी होनी चाहिए जिससे पेट्रोल डीजल का उपयोग होने वाले उद्योगों में लागत मूल्य कम आता।

विधायक ललित ने चार वार्डों में 1.72 करोड़ से होने वाले विकास के लिए किया भूमिपूजन

रिसाली (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम रिसाली में विकास कार्य के लिए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर और महापौर शशि सिन्हा ने भूमिपूजन किया। 1 करोड़ 72 लाख 8 हजार से तालपुरी, रूआबांधा उत्तर, रूआबांधा दक्षिण व रूआबांधा पूर्व में विकास कार्य होंगे। विधायक ललित ने नारियल तोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भूमिपूजन अवसर पर कहा कि संकल्प पत्र में किए घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार रिसाली को नए कलेवर में आम जनता को समर्पित करेगी। रिसाली की दशा एव दिशा जल्द बदलेगी। विधायक ललित ने कहा कि विकास के नए शोषण के तहत उन्होंने आज वार्ड क्र. 01 से



लेकर 04 तक भूमिपूजन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश कार्य वही है जिन्हें जनता ने मांग की है। विकास कार्य के लिए किसी तरह की पैसे की कमी नहीं होगी। भूमिपूजन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू, महापौर परिषद की सदस्य ममता यादव, पार्षद सारिका साहू, सविता डबस, डॉ. सीमा साहू, सरिता देवांगन, धर्मेन्द्र भगत, शोला नारखेड़े, माया यादव समेत मण्डल अध्यक्ष अनूपम साहू, राजू जंघेल समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

पूरे 40 वार्डों में होगा कार्य

भूमिपूजन कार्यक्रम में विधायक ललित ने कहा कि वें पूरे 40 वार्डों में भूमिपूजन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया है। वें शहर के अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि जल्द ही रिसाली निगम क्षेत्र में कॉलेज और नालंदा परिसर का भी निर्माण किया जाएगा।

चार वार्डों में होंगे यह कार्य

वार्ड क्र. 01 तालपुरी में नाली के उपर कव्हर, फेंसिंग वर्क, डोम शेड, कव्हर ड्रेन का कार्य 30.22 लाख से पूर्ण किया जाएगा। इसी तरह वार्ड क्र 02 रूआबांधा उत्तर में बाउंड्रीवाल, कम्यूनिटी हॉल, पेवर् ब्लाक, रोड चौड़ीकरण के लिए शासन ने कुल 69.28 लाख रूपए स्वीकृत की है।

पीएम श्री विद्यालय पहुंचकर पुरन्दर मिश्रा, जाना शिक्षा व्यवस्था का हाल



रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरन्दर मिश्रा ने पीएम श्री शासकीय पूर्व बुनियादी प्राथमिक शाला, खन्हारडीह का निरीक्षण कर विद्यालय की शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने विद्यालय के शिक्षकों से विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए शिक्षण व्यवस्था, उपलब्ध संसाधनों, अधोसंरचना तथा विद्यालय की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। शिक्षकों द्वारा रखे गए सुझावों और मांगों को गंभीरता से सुने हुए उन्होंने आवश्यक सुविधाओं के शीघ्र विस्तार एवं समस्याओं के त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया।

मवेशी धर-पकड़ अभियान, 12 मवेशी पकड़ रेवाडीह एवं कन्हारपुरी कांजी हाउस छोड़े

राजनांदगांव (विश्व परिवार)। पशु मालिकों की लापरवाही से मवेशी निगम सीमाक्षेत्र के चौक चौराहों में घुमते रहने एवं बैठे रहने से यातायात बाधित होने एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। आमजनो एवं मवेशियो को दुर्घटना से बचाने नगर निगम द्वारा मवेशी धर पकड़ अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही निदान 1100 तथा मुख्यमंत्री हेल्प लाईन में प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी मवेशी पकड़ा जाता है तथा बीमार मवेशी ईलाज के लिए गौशाला पिंजरापोल तथा आरोग्यम गौशाला छोड़ा जाता है एवं रात में टीम द्वारा मवेशी हकाला भी जाता है। मवेशी धर-पकड़ अभियान के तहत कल व आज में चौक चौराहो से 12 घुमंतु एवं बैठे मवेशी पकड़कर रेवाडीह व कन्हारपुरी कांजी हाउस पहुंचाया गया। जहाँ गंज मण्डो से बचे पत्त सब्जी लाकर मवेशियो को



खिलाया जा रहा है। मवेशियों को पकड़ने शासन व प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर निगम की घुमंतु मवेशियों को पकड़ने निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित टीम चौक चौराहो से घुमंतु मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही के तहत रामदरवार चौक, जी.ई.रोड, मठपारा रोड, इंदिरा नगर, लखोली के पास से 6 मवेशी पकड़ रेवाडीह काजी हाउस छोड़े वही कल गंज चौक, लखोली नाका चौक, राजीव नगर, नंदई, हाट बाजार के सामने, जिला चिकित्सालय के सामने, महामाया चौक, नया बस स्टैण्ड से घुमंतु एवं बैठे 6 मवेशी को पकड़कर कन्हारपुरी कांजी हाउस में रखा गया है।

रोजगार मेला में 13 युवाओं को ऑन द स्पॉट मिला ऑफर लेटर

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में 8 जुलाई को जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा रोजगार कार्यालय परिसर बलौदाबाजार में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 43 आवेदकों का प्राथमिक चयन एवं 13 आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। निजी क्षेत्र में ऑनलाइन आवेदन किया गया 234 पदों की भर्ती हेतु रोजगार मेला का आयोजन किया गया जिसमें 476 आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया, जिसमें से 147 आवेदक साक्षात्कार में भाग लिया गया। रोजगार मेला में नियोजक भारतीय जीवन बीमा बलौदाबाजार द्वारा अधिकतम के 50 पद, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के



1 पद, मैनेजर के 1 पद हेतु 49 आवेदकों द्वारा साक्षात्कार में भाग लिया, जिसमें से 9 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। इसी प्रकार स्त्रध वेंचर्स बलौदाबाजार द्वारा सेल्स के 11 पद, इलेक्ट्रिशियन के 1 पद, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 1 पद, के लिए 25 आवेदकों द्वारा साक्षात्कार में भाग लिया जिसमें से 13 आवेदकों का प्राथमिक चयन एवं 9 आवेदकों को मेला स्थल पर ही ऑफर लेटर प्रदान किया गया।

उरला में हुए ब्लास्ट में तीन मजदूरों की मौत लापरवाही का परिणाम: अहमद

रायपुर (विश्व परिवार)। मंगलवार को श्रीडी फैक्ट्री, उरला में हुए ब्लास्ट में तीन मजदूर भाइयों की दर्दनाक मौत अत्यंत दुःख और चिंताजनक है। इकराम अहमद, प्रभारी - लोक निर्माण विभाग, नगर निगम बिरगांव, रायपुर ने बताया की यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की बड़ी लापरवाही का परिणाम है। लगातार उरला इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं होना यह साबित करता है कि फैक्ट्रियों में सुरक्षा के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि हर बार निर्दोष और मेहनतकश मजदूर ही अपनी जान गंवाते हैं, जबकि जिम्मेदार लोग बच निकलते



हैं। हादसे के बाद कुछ दिनों तक जांच और कार्रवाई का दिखावा किया जाता है, फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सरकार और प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस गंभीर घटना को केवल एक फइल बनाकर बंद न किया जाए, बल्कि दोषी फैक्ट्री प्रबंधन और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी फैक्ट्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी मजदूर की जान इस तरह न जाए। मजदूरों की सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि उनकी बुनियादी अधिकार है इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

छत्तीसगढ़ पेंशनर्स एसोसिएशन ने पुरन्दर मिश्रा से की सौजन्य भेंट

रायपुर (विश्व परिवार)। गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में आज छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरन्दर मिश्रा से सौजन्य भेंट कर आत्मीय मुलाकात की। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष श्री पंकज नायक के नेतृत्व में उपस्थित प्रतिनिधिमंडल ने कि सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने लंबे अनुभव, ज्ञान और सेवा भावना के माध्यम से समाज के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि समाज निर्माण एवं नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में पेंशनर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उनके अनुभवों का लाभ जनहित में निरंतर मिलना चाहिए। बैठक के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। विधायक ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और जनहित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक पहल एवं निरंतर संवाद का विश्वास दिलाया।



विधायक पुरन्दर मिश्रा ने संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने लंबे अनुभव, ज्ञान और सेवा भावना के माध्यम से समाज के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि समाज निर्माण एवं नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में पेंशनर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और उनके अनुभवों का लाभ जनहित में निरंतर मिलना चाहिए। बैठक के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने भी विभिन्न सामाजिक एवं जनकल्याणकारी विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। विधायक ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और जनहित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक पहल एवं निरंतर संवाद का विश्वास दिलाया।

लगातार वर्षा के बाद धान की बुआई एवं रोपाई में तेजी लाने की सलाह

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी किया वैज्ञानिक कृषि सलाह बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। जिले में 1 जुलाई से 6 जुलाई के दौरान हुई लगातार एवं व्यापक वर्षा के फलस्वरूप धान की खेती के लिए पर्याप्त नमी एवं जल उपलब्ध हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र, भाटापारा एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए धान की बुआई, रोपाई, बीजोपचार, उर्वरक प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण संबंधी विस्तृत वैज्ञानिक सलाह जारी की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वर्ष मानसून का आगमन सामान्य से कुछ विलंब से हुआ, किन्तु वर्तमान में जिले के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होने से धान की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। जिन किसानों को धान नर्सरी तैयार है, वे खेतों में मचाई कर शीघ्र रोपाई प्रारंभ

कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विभाग ने किसानों के लिए जारी किया वैज्ञानिक कृषि सलाह

बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। जिले में 1 जुलाई से 6 जुलाई के दौरान हुई लगातार एवं व्यापक वर्षा के फलस्वरूप धान की खेती के लिए पर्याप्त नमी एवं जल उपलब्ध हो गया है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र, भाटापारा एवं कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए धान की बुआई, रोपाई, बीजोपचार, उर्वरक प्रबंधन एवं खरपतवार नियंत्रण संबंधी विस्तृत वैज्ञानिक सलाह जारी की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि इस वर्ष मानसून का आगमन सामान्य से कुछ विलंब से हुआ, किन्तु वर्तमान में जिले के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होने से धान की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन चुकी हैं। जिन किसानों को धान नर्सरी तैयार है, वे खेतों में मचाई कर शीघ्र रोपाई प्रारंभ



करें। जिन किसानों के पास नर्सरी उपलब्ध नहीं हैं, वे लेही विधि से अंकुरित बीजों की ड्रम सीडर अथवा छिटकवा विधि से बुआई कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि सीधी बुआई करने वाले किसान 15 जुलाई तक तथा रोपाई एवं बियासी पद्धति अपनाने वाले किसान 30 जुलाई तक अपना कार्य पूर्ण कर लें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में बुआई या रोपाई हेरली पर्व तक भी करनी पड़े तो उत्पादन पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ेगा।

आयुक्त सबित मिश्रा के निर्देशन में चाइस सेंटर संचालकों एवं सहायक राजस्व अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

सेवा सेतु परियोजना के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस एवं राशन कार्ड की ऑनलाइन सेवा का क्रियान्वयन रायपुर (विश्व परिवार)। शासन की महत्वाकांक्षी 'सेवा सेतु' परियोजना के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस एवं राशन कार्ड से संबंधित ऑनलाइन सेवाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु नगर निगम आयुक्त श्री सबित मिश्रा के निर्देशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण उप आयुक्त (राजस्व) के मार्गदर्शन में चिप्स कार्यालय के श्री आशीष साहू एवं ईडीएम श्रीमती कीर्ति की टीम द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी चाइस सेंटर संचालक तथा नगर निगम के सभी 10 जनों के सहायक राजस्व अधिकारी



(एआरओ) उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के लिए केवल दो आवश्यक दस्तावेज-पहचान पत्र (आई-कार्ड) एवं संपत्ति से संबंधित दस्तावेज-ही लिए जाएं। आवेदकों से अनावश्यक दस्तावेज न मांगे जाएं तथा किसी भी स्थिति में आवेदन को बिना उचित कारण अनावश्यक रूप से वापस न किया जाए। इस दौरान चाइस सेंटर संचालकों एवं जोन स्तर के

अधिकारियों द्वारा बताई गई व्यावहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का विप्स एवं ईडीएम की टीम के माध्यम से निराकरण भी किया गया। प्रशिक्षण में आवेदन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सेवा सेतु से संबंधित तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर एवं ई-मेल आईडी भी जारी की गई है- हेल्पलाइन नंबर: 0771-2992035।

एनएचएम कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से की सौजन्य भेंट

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम. कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल से सौजन्य भेंट कर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा 13 जून 2026 को आयोजित प्रदेश स्तरीय एन.एच.एम. महासम्मेलन में की गई घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि महासम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्रेड पे समिति के गठन, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, नई मानव संसाधन नीति, स्थानांतरण नीति, अनुकंपा नियुक्ति, कैंसलेश इलाज की सुविधा, मुख्यमंत्री जी का मंच से किये गए घोषणा अनुसार कर्मचारियों का हड़ताल अर्थात् का वेतन सहित एन.एच.एम. कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक



घोषणाएँ की गई थीं। इन घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन से प्रदेश के 18 हजार से अधिक एन.एच.एम. कर्मचारियों को लाभ मिलेगा तथा राज्य की स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिक सशक्त एवं प्रभावी होंगी। संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर आदेश जारी किए जाएं, ताकि कर्मचारियों को घोषणाओं का लाभ जल्द प्राप्त हो सके।

रायपुर विकास प्राधिकरण की संपत्तियों की पूरी तरह ऑनलाइन घर बैठे करें आवेदन और बुकिंग

रायपुर (विश्व परिवार)। रायपुर विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) ने अपनी संपत्तियों की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आम नागरिक बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए घर बैठे ही आर.डी.ए. की वेबसाइट https://rdaraipur.cgstate.gov.in/ के माध्यम से पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया के तहत संपत्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं बुकिंग कर सकेंगे। आर.डी.ए. द्वारा पिछले लगभग 121 संपत्तियों को ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है। इनमें कमल विहार एवं रावभाटा सहित प्राधिकरण की प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की संपत्तियाँ शामिल हैं। कमल विहार एवं आवासीय फ्लैट्स तथा आवासीय एवं व्यावसायिक



भूखंड उपलब्ध हैं, जबकि रावभाटा में व्यावसायिक संपत्तियाँ बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय संपत्तियों का निर्माण किया गया है, ताकि प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को उनकी आवश्यकता एवं सामर्थ्य के अनुरूप आवास उपलब्ध कराया जा सके। इच्छुक आवेदक अपनी बुकिंग के अनुसार उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी प्राप्त कर

वैबसाइट https://rdaraipur.cgstate.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। संपत्तियों की ऑनलाइन बुकिंग के साथ-साथ अब हितग्राही घर बैठे ही वेबसाइट के माध्यम से मंटेनेंस चार्ज का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकेंगे, जिससे नागरिकों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और सेवाएँ अधिक सुविधाजनक एवं समयबद्ध बनेंगी।

राजनांदगांव। डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए इच्छुक एवं पात्र कृषकों से 31 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है। उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ भरे हुए आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अधिकतम दो पेज में सफलता की कहानी छयाचित्र व वीडियो सीडी संलग्न करना होगा। पुरस्कार वितरण राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 2026 के अवसर पर किया जाएगा।

‘बस्तर अंजोर’ से विकसित छत्तीसगढ़ के विज्ञान को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री साय

■ मुख्यमंत्री ने किया छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 प्रेमवर्क का विमोचन, बस्तर के समग्र एवं परिणामोन्मुख विकास के लिए ‘बस्तर अंजोर’ पहल का शुभारंभ



रायपुर (विश्व परिवार)। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की उपस्थिति में राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. 2.0 प्रेमवर्क का विमोचन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. राज्य एवं जिला संकेतक प्रेमवर्क 2.0 तथा मेटाडेटा हैंडबुक का भी विमोचन किया गया। साथ ही बस्तर संभाग के समावेशी, अभिसरण आधारित और मापनीय विकास के लिए तैयार की गई अभिनव पहल ‘बस्तर अंजोर’ की भी शुरुआत की गई।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए

योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, सटीक डेटा और परिणाम आधारित मॉनिटरिंग अत्यंत आवश्यक है। एस.डी.जी. 2.0 प्रेमवर्क शासन को साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर-विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल ‘विकसित छत्तीसगढ़ @2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल विकास योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि उनके वास्तविक प्रभाव

को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। एस.डी.जी. 2.0 के माध्यम से विकास की प्रगति को अधिक पारदर्शी, मापनीय और जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

नए एस.डी.जी. 2.0 प्रेमवर्क के अंतर्गत राज्य स्तर पर संकेतकों की संख्या 275 से बढ़ाकर 343 तथा जिला स्तर पर 82 से बढ़ाकर 99 कर दी गई है। इससे विकास कार्यों की अधिक व्यापक, सटीक और वैज्ञानिक निगरानी संभव होगी। मेटाडेटा हैंडबुक में प्रत्येक संकेतक की गणना पद्धति एवं रिपोर्टिंग प्रणाली को मानकीकृत किया गया है, जिससे पूरे राज्य में डेटा की

गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

इस अवसर पर राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने ‘बस्तर अंजोर’ की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यह अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित विकास मॉडल है, जिसे बस्तर संभाग को देश का सर्वाधिक विकसित जनजातीय क्षेत्र बनाने के संकल्प को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि ‘बस्तर अंजोर’ के 3+4 मॉडल के अंतर्गत जिला स्तर की तीन प्रमुख पहल - नियद नेह्लानर 2.0, बस्तर प्रेमवर्क - एस.डी.जी. 2030, विकसित छत्तीसगढ़ @2047, आकांक्षी जिला एवं विकासखंड कार्यक्रम से किया गया है। इसका उद्देश्य अतिरिक्त संसाधनों के बिना बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त करना है।

कांग्रेस की ‘सद्दा सरकार’ के संरक्षण में पल रहे घोटालेबाज अब पाताल से भी खींचे जा रहे : भाजपा

■ ‘भूपेश कका का वरदहस्त अब काम नहीं आया; कानून का शिकंजा कस चुका है, छत्तीसगढ़ की जनता को पाई-पाई का हिसाब देना होगा’



रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने महादेव आनंदाइन बेटिंग ऐप के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइण्ड सोरभ चन्द्राकर की ओमान में हुई गिरफ्तारी के मद्देनजर तत्कालीन के चेहेरे बेनकाब होकर रहेंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भूपेश बघेल की सरकार ‘सद्दा सरकार’ के रूप में याद की जाएगी। जिस भिलाई के लड़के ने 2019 में हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया, वह तत्कालीन

कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे फल-फूल रहा था। क्या यह मुमकिन है कि बिना राजनीतिक संरक्षण और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के वरदहस्त के बिना इतना बड़ा सद्दा और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल साल-दर-साल चलता रहा? छत्तीसगढ़ की जनता सब समझ रही है कि बस्तर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती क्यों की जा रही थी! डॉ. मिश्रा ने कहा कि जब भाजपा और केन्द्रीय एजेंसियां इस घोटाले की परतें खोल रही थीं, तब कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक ट्रेंच का नाम देकर छत्ती पीट रहे थे। आज जब इंटरपोल के रेड नोटिस पर ओमान पुलिस ने मास्टरमाइण्ड को दबोचा है, तो कांग्रेस के खेमे में सनाटा पसर है! यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के उन लाखों युवाओं के साथ न्याय की शुरुआत है, जिनका भविष्य इस सिण्डिकेट ने बर्बाद किया।

मंडल रेल प्रबंधक ने रायपुर-दुर्ग रेलखंड व दुर्ग स्टेशन के री-डेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण किया



रायपुर। रायपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने 08 जुलाई 2026 को जनतावादी एक्सप्रेस (रायगढ़-गोंदिया) से रायपुर रेलवे स्टेशन से दुर्ग रेलवे स्टेशन तक रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने रायपुर से दुर्ग तक लोकोमोटिव में निरीक्षण के माध्यम से रेल अवसंरचना, संरक्षा एवं परिचालन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी सहित मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन री-डेवलपमेंट एजेंसी के मैनेजर भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित व्यवस्थाओं एवं कार्यों का चलती ट्रेन में एवं दुर्ग स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रेल संरक्षा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मानसून के दृष्टिगत आवश्यक सेफ्टी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया।

सहयोग केन्द्र में वित्त मंत्री चौधरी ने किया कार्यकर्ताओं से संवाद

रायपुर (विश्व परिवार)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय (कुशाभूषण ठाकरे परिसर) में बुधवार को सहयोग केन्द्र में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्री चौधरी ने सहयोग केन्द्र पहुंचे 300 से भी अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं व शिकायतों को सुना। पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपनी मांगों और व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्याएँ लेकर पहुंचे थे। श्री चौधरी ने बेहद संवेदनशीलता के साथ इस दौरान प्रायः 100 से अधिक आवेदनों का एक-एक कर अवलोकन किया। आवेदनों में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा, पेंशन योजनाएँ,



राजस्व मामले, शिक्षा, स्वास्थ्य सहायता और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे शामिल थे। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री चौधरी ने तत्परता दिखाते हुए कई मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से फ़ोन पर निर्देशित किया कि आम जनता के काम में किसी भी प्रकार की हिलाई या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी आवेदनों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बाद में मीडिया से चर्चा

विक्रम प्रताप सिंह भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने

बीरगांव। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल (बी जे एम टी यू सी) ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए में बड़ा निर्णय लिया है। जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री आचार्य के अनुशंसा एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा के अनुशंसा पर विक्रम प्रताप सिंह को भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वही विक्रम प्रताप सिंह ने इसके अलावा भी कई बड़ी जिम्मेदारियां का निर्वहन कर रहे हैं वही विक्रम प्रताप सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को ही संगठन ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है वहीं उन्होंने कहा कि पैराशूट की राजनीति करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं तो जमीनी स्तर में काम कुछ नहीं वही विक्रम प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष,केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसूख मंडाविया राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव तारा पाठक, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दीपक पाण्डेय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने कम करने की इतनी बड़ी जवाबदारी एवं जिम्मेदारी दी है जिसमें संगठन के पदाधिकारी का सदा आभारी रहूंगा वहीं उन्होंने मजदूर हित एवं संगठन को मजबूत बनाने हेतु संकल्प लिया।

श्रीडी उद्योग दुर्घटना प्रबंधन के साथ सरकार की भी आपराधिक लापरवाही : दीपक बैज

रायपुर (विश्व परिवार)। उरला के श्रीडी फैक्ट्री में ब्लास्ट से 3 मजदूरों की मौत, बड़ी संख्या में मजदूरों के घायल होने पर गहरा दुःख प्रकट करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह हादसा उद्योग प्रबंधन के साथ सरकार में अनेकों लोगों के झुलसकर घायल होने की सूचना है, मृतकों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है। घायलों के बेहतर इलाज की समुचित व्यवस्था कर न्यायिक जांच कराई जाए और मृतकों के परिारण को एक-एक करोड़ और घायलों को 50-50 लाख मुआवजा



दे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि ढाई साल में प्रदेश के औद्योगिक दुर्घटनाओं में 300 से अधिक मजदूरों की जान गयी है। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, कुछ महीना पहले सक्ती जिले में डभरा थाना क्षेत्र के सिन्धीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 मजदूरों की मौत एवं 50 से अधिक मजदूरों को घायल हुये थे।

आईआईटी भिलाई ने विकसित की जंग रोधी और स्मार्ट बहु-कार्यात्मक कोटिंग

■ आईआईटी भिलाई-आईआईटी पटना के शोधकर्ताओं की बड़ी उपलब्धि



रायपुर (विश्व परिवार)। धातुओं में जंग लगने और आग से होने वाली क्षति से उद्योगों को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान, सुरक्षा संबंधी जोखिम तथा रखरखाव लागत की चुनौती का समाधान खोजते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई (आईआईटी भिलाई) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (आईआईटी पटना) के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट बहु-कार्यात्मक पॉलिमर कोटिंग विकसित की है। यह नई कोटिंग धातु की सतहों को जंग से सुरक्षित रखने के साथ-साथ अग्नि-सुरक्षा भी प्रदान करती है। शोध के परिणाम विश्व की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका एडवॉन्स्ड फंक्शनल मैटेरियल्स (Advanced Functional Materials) में प्रकाशित हुए हैं।

यह शोध आईआईटी भिलाई के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजीव

बनर्जी के नेतृत्व में किया गया। शोध दल में निशिकांत सिंह, स्वरूप मैती, सौमेन घोष, सुब्रत चट्टोपाध्याय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

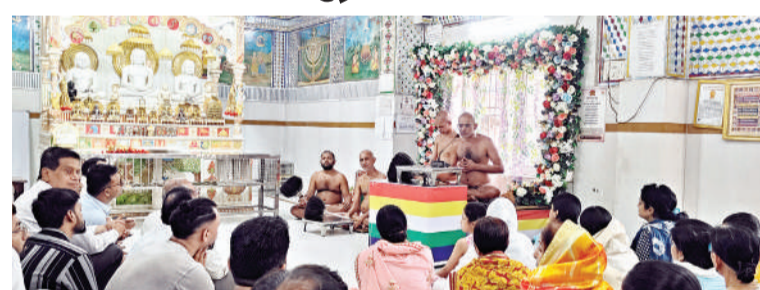
शोधकर्ताओं के अनुसार वर्तमान में उपयोग में आने वाली अधिकांश सुरक्षात्मक कोटिंग्स केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, जिसके कारण व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई परतों अथवा अतिरिक्त रासायनिक उपचारों की आवश्यकता पड़ती है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए शोध दल ने फंक्शनल और फ्लोरोन आधारित एक विशेष पॉलिमर कोटिंग विकसित की है।

राजधानी रायपुर में जैन मुनि संघ का भव्य मंगल प्रवेश, गुरुवर के जयकारों से गूंज उठा शंकर नगर

रायपुर (विश्व परिवार)। राजधानी के जैन समाज के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और अत्यंत सौभाग्यशाली रहा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 आगम सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 पुनीत सागर जी महाराज, एलक श्री धैर्य सागर जी एवं एलक श्री स्वागत सागर जी महाराज संसंध का फणभंडीह दिगंबर जैन मंदिर से विहार कर श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर, शंकर नगर की धरा पर मंगल प्रवेश हुआ।

मुनि संघ के शंकर नगर आगमन पर समूचा जैन समाज भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने अपार श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ गुरुवर के पावन चरणों को धोकर पाद प्रक्षालन कर एवं आरती उतारकर अपने जीवन को धन्य बनाया। साक्षात् मोक्ष मार्ग के इन दिगंबर संतों के दर्शन पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाव उमड़ पड़ा।

मंगल प्रवेश के दौरान शंकर नगर दिगंबर जैन समाज में अभूतपूर्व उत्साह देखने को



मिला। समाज के अबाल-वृद्ध, महिलाएँ और युवा हाथों में धर्मध्वजा लिए गुरुदेव के जयकारे लगाते हुए झूमते-नाचते नजर आए। पूरा वातावरण ‘आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय’ और ‘मुनि संघ की जय’ के गगनभेदी नारों से गुंजायमान हो उठा। इसी पावन उत्साह के साथ मुनि संघ को गाजे-बाजे के साथ चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर जी में प्रवेश कराया गया।

मंगल प्रवेश के उपरंत धर्मसभा को संबोधित करते हुए परम पूज्य मुनि श्री 108 आगम सागर जी महाराज ने अपनी दिव्यवाणी से अमृत प्रवचन दिए। उन्होंने उपस्थित धर्मसभा को आत्म-कल्याण और सम्यक्

के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही मुनि संघ ने मंदिर जी में विराजमान अतिथिकारी प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन व वंदना कर जगत के कल्याण की मंगल भावना भाई। सकल दिगंबर जैन समाज, रायपुर एवं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, मालवीय रोड मालवीय रोड,शंकर नगर मंदिर प्रबंधन ने समस्त राजधानी वासियों से आत्मीय अपील की है कि इस पावन वाच्य योग/मंगल आगमन के दौरान प्रतिदिन मंदिर जी पहुंचकर गुरु दर्शन, अमृत प्रवचन, वैयावृत्ति और आहार चर्या में बद्ध-चढ़कर हिस्सा लें तथा अधिक से अधिक चौके लगाकर अपने जैनत्व व जीवन को सार्थक बनाएं।

दपूमरे के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर स्थापित है आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम

■ आधुनिक सेंसर आधारित तकनीक से बाढ़ के दौरान निगरानी हुई अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय

रायपुर (विश्व परिवार)। मानसून के दौरान रेलवे पुलों पर नदियों के जलस्तर की सतत एवं सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम को अपनाया गया है। सेंसर आधारित यह अत्याधुनिक प्रणाली वर्तमान में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर स्थापित की गई है। यह प्रणाली 24 घंटे रियल-टाइम में जलस्तर की निगरानी करके हुए संचालित एवं निर्बाध रेल परिचालन

सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पूर्व में नदियों के जलस्तर का आकलन पारंपरिक मीटर गेज प्रणाली के माध्यम से किया जाता था, जिसमें मैनुअल रीडिंग लेने के कारण सूचना प्राप्त होने में विलंब तथा त्रुटि की संभावना बनी रहती थी। अचानक निगरानी सुनिश्चित करने में समय पर जानकारी उपलब्ध न होने से रेलवे ट्रैक एवं पुलों की संरक्षा का त्वरित आकलन करना चुनौतीपूर्ण होता था। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आधुनिक वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। यह प्रणाली सेंसर आधारित तकनीक के माध्यम से पुलों पर लगे जलस्तर संकेतकों की निरंतर निगरानी करती है



तथा ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से एकीकृत रहती है। जैसे ही नदी का जलस्तर पूर्व निर्धारित चेतावनी अथवा खतरे के स्तर तक पहुंचता है अथवा उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, सिस्टम त्वरित: संबंधित अधिकारियों

एवं अभियंताओं के मोबाइल फोन पर तत्काल एसएमएस अलर्ट भेज देता है। इससे आवश्यक सुरक्षा उपाय समय रहते लागू किए जा सकते हैं तथा रेल परिचालन को संरक्षित बनाए रखने में सहायता मिलती है।

इस प्रणाली में संबंधित सहायक मंडल अभियंता, रेल पथ निरीक्षक (पीडब्ल्यूआई) सहित अन्य अधिकृत अधिकारियों के मोबाइल नंबर पंजीकृत रहते हैं। परिणामस्वरूप जलस्तर में होने वाले त्वरित महत्वपूर्ण परिवर्तन की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों तक पहुंच जाती है, जिससे त्वरित निर्णय लेने और आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा होती है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जिन 12

महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर वाटर लेवल मॉनीटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, वे निम्नानुसार हैं—

1. झारसुगुड़ा: ईब स्टेशनों के मध्य ईब नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 184 अप।
2. ईब: ब्रजराजनगर स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 182 अप।
3. भूपदेवपुर: राबटर्स स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 86 अप।
4. कोरवा: गेवरा रोड स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 63 डाउन।
5. नैलाडूचांपा स्टेशनों के मध्य हसदेव नदी पर रेलवे पुल क्रमांक 46 डाउन।
6. जयरामनगर: अकलतरा स्टेशनों के मध्य रेलवे पुल क्रमांक 12 मिडल।

डिंपल्स कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा गालों में स्थायी डिंपल्स

कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर

फोन: 9827143060/8871003060

GST ITR

फाइल बनवाएं मात्र 500/-

हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार हैं।

Income Tax Return - GST रिटर्न - TDS Return

CMA Data - MSME Registration - Balance Sheet

मोबाइल रिपोर्ट GST Return - पूरा लाइसेंस

संस्क: शेखर गुप्ता WhatsApp पर बतवाएं

9300755544